RNI No. 58061/93 ▪ वर्ष - 21 ▪ अंक - 84 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- | बेंगलूरु » शुक्रवार » 17-10-2025 | ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 नीतीश के नेतृत्व में एक बार फिर जीत हासिल करेगा राजग : मोहन यादव
6 संवेदनशीलता से ही रोके जा सकेंगे बाल अपराध
7 प्रेम, बुद्धिमत्ता और नारी शक्ति का उत्सव है : कावेरी कपूर

फर्स्ट टेक

सीरियाई रक्षा मंत्रालय की बस में बम विस्फोट

दमिश्क (सीरिया)/एपी। सीरिया के पूर्वी हिस्से में बृहस्पतिवार को रक्षा मंत्रालय की एक बस में बम विस्फोट हुआ, जिसमें चार सैनिक मारे गए और अन्य घायल हो गए। एक मंत्री ने इसकी जानकारी दी। तेल मंत्री मोहम्मद अल-बशीर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा सैनिक तेल सुविधा में सुरक्षा कर्मियों के रूप में तैनात थे और ड्यूटी पर जाते समय उनकी बस में विस्फोट हुआ। सरकारी अल-इखबरिया टीवी ने बताया कि विस्फोट पूर्वी शहरों देइर अल-ज़ौर और मायादीन को जोड़ने वाली सड़क पर हुआ। खबर में बताया गया है कि सैनिक इराक की सीमा से लगे तेल समृद्ध क्षेत्र में एक प्रतिष्ठान में तैनात थे। किसी ने भी हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है लेकिन यह इलाका इस्लामिक स्टेट(आईएस) समूह के 'स्लीपर सेल' का गढ़ माना जाता है। आईएस को 2019 में सीरिया में पराजित किया गया था। आईएस, जिसने एक समय पर सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर रखा था।

इजराइली हमले में यमन के हूती विद्रोहियों के सेना प्रमुख की मौत

दुबई/एपी। यमन के हूती विद्रोहियों के नेताओं को निशाना बनाकर अगस्त में किए गए इजराइली हमले में समूह के सेना प्रमुख की मौत हो गई। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। गाजा पट्टी में संघर्षविराम होने के बावजूद हूती विद्रोहियों और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। हूती विद्रोहियों ने स्वीकार किया है कि इजराइली हमले में मेजर जनरल मुहम्मद अब्दुल करीम अल-गमारी की मौत हो गई है, जिसे देश में एक दशक से जारी युद्ध में उसकी भूमिका के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हूती विद्रोहियों के सेना प्रमुख की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि अल-गमारी की मौत हमले में लगी चोटों के कारण हुई। काट्ज ने 28 अगस्त को किए गए हमलों का हवाला देते हुए यह बात कही। तब हुए हमले में हूती विद्रोही समूह के प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी की भी मौत हो गई थी।

17-10-2025	18-10-2025
सूर्यास्त 5:59 बजे	सूर्योदय 6:10 बजे

BSE	NSE
83,467.66	25,585.30
(+862.23)	(+261.75)

सोना	चांदी
12,783 रु.	167,199 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

क्या-क्या बाँटोगे

प्रतिबंधित एयरस्पेस हुए,
अवरोध बने सीमाओं पे।
नदियों का जल भी बाँट लिया,
झगड़ा वृक्षों की छाँहों पे।
सागर के पानी पर लकीर,
भूगर्भ युद्ध के दावों पे।
बादल खुशबू अरदास करे,
अंकुश ना लगे हवाओं पे।।

इक्कीसवीं सदी भारत की, 2047 तक 'विकसित भारत' का सपना साकार होगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कुरनूल/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि 21वीं सदी 140 करोड़ भारतीयों की है और 2047 तक 'विकसित भारत' का सपना साकार हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर बिजली क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया।

भारत के 'मेक इन इंडिया' पारिस्थितिकी तंत्र की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा, हमने 'ऑपरेशन सिंदूर' में घरेलू स्तर पर निर्मित 'उपकरणों' की ताकत देखी, जो 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ चलाया गया सैन्य अभियान था।

प्रधानमंत्री ने आयकर छूट की सीमा 12 लाख रुपए किए जाने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ढांचे में सुधार जैसे हालिया घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि नागरिक-केंद्रित विकास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। मोदी ने आंध्र प्रदेश के लिए 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के बाद यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, जैसा कि (आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री) चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, 2047 में आजादी के शताब्दी वर्ष तक 'विकसित भारत' का सपना साकार हो जाएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 21वीं सदी भारत की होगी। 21वीं सदी 140 करोड़ भारतीयों की है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत को 21वीं सदी के नए विनिर्माण केंद्र के रूप में देख रही है और इस सफलता का आधार 'आत्मनिर्भर भारत' का दृष्टिकोण है, जबकि आंध्र प्रदेश इसकी सफलता का प्रमुख केंद्र बन रहा है।

मोदी ने आरोप लगाया कि 11 साल पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब प्रति व्यक्ति बिजली की औसत खपत 1,000 यूनिट से भी कम थी, लेकिन उस समय देश को 'ब्लैकआउट' जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था और ''हमारे गांवों में बिजली के खंभे तक नहीं थे। उन्होंने कहा, मित्रो, स्वच्छ ऊर्जा से लेकर देश के कुल ऊर्जा उत्पादन तक, भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान बना रहा है।

ट्रंप से डरे हुए हैं प्रधानमंत्री : राहुल

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए दावे को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ट्रंप से डरे हुए हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, वह (मोदी) मेरे मित्र हैं। हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरे मित्र ने मुझे आश्वासन दिया है कि रूस से कोई तेल खरीद नहीं होगी। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। उन्होंने ट्रंप को यह निर्णय लेने दिया और घोषणा करने दी कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी बार-बार आलोचना के बावजूद ट्रंप को सराहना वाले संदेश भेजते रहते हैं।

सभी भगोड़ों को वापस लाने के लिए निशिचत प्रणाली जरूरी : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्थिक अपराधियों, साइबर अपराधियों, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों और अन्य सभी भगोड़ों के प्रति कठोर रवैया अपनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली के दायरे में लाया जा सके।

सीबीआई द्वारा यहां आयोजित 'भगोड़ों का प्रत्यर्पण – चुनौतियां और रणनीतियां' विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, शाह ने सभी राज्यों से कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की जेल कोठरी स्थापित करने का भी आग्रह किया ताकि विदेशी अदालतों में भगोड़ों द्वारा दी जाने वाली निम्न स्तर की जेल की दलीलों को खारिज किया जा सके। उन्होंने कहा कि न केवल भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद के विरुद्ध, बल्कि भारत के बाहर से सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध भी कतई बर्दाश्त नहीं करने का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी भगोड़ों को कानून के दायरे में लाने और इसके लिए एक निश्चित तंत्र स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा, चाहे वे आर्थिक अपराधी हों, साइबर अपराधी हों, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हों या संगठित अपराध नेटवर्क का हिस्सा हों, प्रत्येक भगोड़े के विरुद्ध कठोर रवैया अपनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली के समक्ष लाया जा सके। इसके लिए समय आ गया है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने इसके लिए अचूक उपाय किए हैं।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पुणे/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' को भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए कहा कि इस मिशन के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए गए अधिकतर उपकरण स्वदेशी थे। सिंह ने कहा कि भारत ने अब ''उस बाधा को तोड़ दिया है'' जो आजादी के बाद से बनी हुई थी और सरकार ने देश के भीतर हथियारों के निर्माण को जोर शोर से बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक घरेलू रक्षा विनिर्माण को तीन लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना और रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है।

केंद्रीय मंत्री ने पुणे में 'सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी' के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, हमने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में यह मुश्किल था क्योंकि हम पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे थे। आजादी के बाद से हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। हमारे लिए विदेशों से रक्षा उपकरण खरीदना एक जरूरत बन गई थी और स्वदेशी उत्पादन लगभग न के बराबर था। मंत्री ने कहा कि भारत ने अब ''उस बाधा को तोड़ दिया है'' जो आजादी के बाद से बनी हुई थी। उन्होंने कहा, हमने देश में ही हथियारों के निर्माण को जोर शोर से बढ़ावा दिया है। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि देश रक्षा खरीद के मामले में एक सुविधाजनक स्थिति में पहुंच गया था।

जलवायु और तकनीकी बदलावों के बीच नई मानवाधिकार चुनौतियां सामने आ रहीं : कोविंद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार को आगाह किया कि तेजी से हो रहे तकनीकी और पर्यावरणीय बदलाव मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं और खासकर अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों तथा जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन का सामना कर रहे लोगों के लिए अधिक चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा, आर्थिक प्रगति हमेशा मानवीय गरिमा के साथ-साथ चलनी चाहिए।

कोविंद ने कहा, जलवायु परिवर्तन अब केवल एक पर्यावरणीय चिंता नहीं रह गया है, बल्कि यह मानवाधिकारों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बनता जा रहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 32वें स्थापना दिवस और जेल में बंद कैदियों के मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए, कोविंद ने कहा कि भारत की प्रगति को केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी मापा जाना चाहिए कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों की गरिमा और कल्याण को कैसे बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि भारत ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत संवैधानिक और संस्थागत ढांचा तैयार किया है, लेकिन सच्ची प्रगति करुणा और समावेश पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, मानवाधिकार केवल वैधानिक अधिकार नहीं हैं, बल्कि एक गहन नैतिक और सभ्यतागत चेतना की अभिव्यक्ति हैं।

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि धर्म, करुणा और न्याय के आदर्शों में निहित भारत की सांस्कृतिक विरासत, मानवीय गरिमा के प्रति उसके दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करती रहती है।

पिछले तीन दशकों में कमजोर लोगों को आवाज देने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रशंसा करते हुए, कोविंद ने कहा कि हिरासत में न्याय, बंधुआ मजदूरी, तस्करी और महिलाओं, बच्चों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए आयोग के प्रयासों ने ''राष्ट्र की अंतरात्मा पर एक अमिट छाप'' छोड़ी है। जेल सुधारों के विषय पर, उन्होंने कहा, हिरासत में बंद व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा या अमानवीय व्यवहार हमारे संवैधानिक और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है।

रूसी हमलों से यूक्रेन में घना अंधेरा छाया

जेंलेंस्की ने ट्रंप से मदद की गुहार लगायी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कीव/एपी। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों से हमला किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और अधिक अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली एवं लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग करने की तैयारी कर रहे हैं।

यूक्रेन की राष्ट्रीय ऊर्जा संचालक कंपनी, यूक्रेनेर्गो ने बताया कि ड्रोन एवं मिसाइल हमलों के बाद आठ यूक्रेनी क्षेत्रों में बिजली काटनी पड़ी। देश की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी, डीटीईके ने राजधानी कीव में बिजली गुल होने की सूचना दी और कहा कि हमलों के कारण उसे मध्य पोल्टावा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस निष्कर्षण रोकना पड़ा।

जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 300 से ज़्यादा ड्रोन और 37 मिसाइलें दागीं। उन्होंने रूस पर क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल करने और ग्रिड की मरम्मत में लगे आपातकालीन कर्मचारियों एवं इंजीनियरों को निशाना बनाने के लिए एक ही लक्ष्य पर बार-बार हमले करने का आरोप लगाया।

जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा, इस मौसम में, रूसी हर दिन हमारे ऊर्जा ढांचे पर हमला कर रहे हैं। जेलेंस्की के शुक्रवार को ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ बैठक से पहले बृहस्पतिवार को अमेरिका पहुंचने की उम्मीद है।

ट्रंप का दावा

मोदी ने रूस से तेल नहीं खरीदने का आश्वासन दिया

वाशिंगटन/भाषा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके ''मित्र'' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप ने साथ ही कहा कि यह कदम यूक्रेन पर आक्रमण रोकने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की दिशा में एक ''बड़ा कदम'' होगा। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत द्वारा रूस से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद जारी रखना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसका भारत और अमेरिका के संबंधों पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ा है। ट्रंप ने बुधवार को अपने 'ओवल' कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका इस बात से ''खुश नहीं'' है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी खरीद से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध के लिए वित्तपोषण में मदद मिलती है।

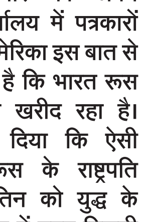

वफादार कांग्रेसी होने के नाते 2019 में भाजपा के प्रस्ताव के बजाय जेल जाना पसंद किया : शिवकुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने 2019 में प्रदेश की कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन सरकार को अस्थिर करने तथा नयी सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद देने के विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की पेशकश से इनकार कर दिया था और ऐसे करने के बजाये उन्होंने जेल जाना पसंद किया था। शिवकुमार ने बुधवार को के एम रघु द्वारा लिखित अपनी पुस्तक ए सिंबल ऑफ लॉयल्टी ''डी के शिवकुमार'' के विमोचन के अवसर पर यह बात कही।

भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने दावा किया है कि 'नवंबर क्रांति' से पहले शिवकुमार ने कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या को संकेतों में यह संदेश दिया है कि अगर सत्ता का हस्तांतरण कर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो उनके पास दूसरा विकल्प भी मौजूद है। राज्य में नवंबर में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे हो रहे हैं और मुख्यमंत्री के बदले जाने की अटकलें हैं, जिसे कुछ लोग नवंबर क्रांति' कह रहे हैं।

शिवकुमार ने कहा, ''मैं कनकपुरा में था, यहां मेरे दोस्त जानते हैं, मैं दौड़ा आया, क्योंकि दस लोग (विधायक) अपना इस्तीफा सौंपने (2019 में) विधानसभा अध्यक्ष के पास गए थे। मैं पांच से छह विधायकों को वापस लाया। उस समय, मुझे दिल्ली से फोन आया। मैं अभी नहीं बताऊंगा कि भाजपा के उस व्यक्ति का नाम जिसने मुझे आयकर आडिटर के फोन पर कॉल किया था। मेरे भाई (पूर्व सांसद डी के सुरेश) भी मेरे साथ थे।''

सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ''यहां एक डीजी थे, उन्होंने भी बात की, वो दूसरे फोन पर थे। दिल्ली से मुझसे पूछा गया कि आप उप-मुख्यमंत्री बनेंगे या जेल जायेंगे। मुझे इन दो विकल्पों में से एक चुनने और विधायकों को वापस भेजने को कहा गया।'' उन्होंने कहा कि उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया। शिवकुमार ने कहा, ''क्या करें। पार्टी के प्रति वफ़ादारी थी, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही (पूर्व प्रधानमंत्री) राजीव गांधी ने मुझे विधानसभा का टिकट दिया, (पूर्व मुख्यमंत्री) एस बंगारप्पा के सहयोग से मुझे मंत्री बनाया। मैं अब तक काफ़ी आगे बढ़ चुका हूं।''

उन्होंने कहा, मैंने (फोन पर भाजपा नेता से) कहा – ''मैं उपमुख्यमंत्री बनने की बजाय जेल जाना पसंद करूंगा। मैं तब (उपमुख्यमंत्री) बन सकता था। पता नहीं राजनीति में क्या होता। लेकिन, मैं अपनी पार्टी, कार्यकर्ताओं, विचारधारा, जिस रास्ते पर मैं आगे बढ़ा, और अपने धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के साथ खड़ा रहा।''

हालांकि, जुलाई 2019 में एच. डी. कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जद(एस) की अस्थिर सरकार गिर गई, क्योंकि 17 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर हो गए। इससे भाजपा के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। शिवकुमार को तीन सितंबर, 2019 को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें उसी वर्ष अक्टूबर में जमानत दे दी थी।

शिवकुमार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, डी.के. शिवकुमार बिना मतलब के कुछ नहीं करते।

वह सिद्दरामय्या और कांग्रेस नेतृत्व को संदेश दे रहे हैं कि अगर उन्हें सत्ता नहीं दी गई तो उनके पास दूसरे विकल्प भी है। वह कांग्रेस के प्रति अपनी वफ़ादारी का भी संदेश दे रहे हैं। भाजपा नेता ने दावा किया, ''वह (शिवकुमार) राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सिद्दरामय्या को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके दावे सच हैं, तो उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्हें किसने, किस समय, किस फ़ोन नंबर से और किसलिए फ़ोन किया था।'' विपक्ष के नेता ने दावा किया, शिवकुमार भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल जा चुके हैं। उनके दावे का इससे कोई लेना-देना नहीं है। अगर वह अब ऐसा कह रहे हैं, तो वह एक संदेश दे रहे हैं; ''यह कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के लिए एक ख़तरा है।''

भाजपा विधायक ने हिंदू लड़कियों को दी सलाह, जिम न जाएं; 'बड़ी साजिश' का हवाला दिया

मुंबई/भाषा। भाजपा विधायक गोपीचंद पडालकर ने बृहस्पतिवार को एक 'बड़ी साजिश' का हवाला देते हुए यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि कॉलेज जाने वाली हिंदू लड़कियों को जिम जाने के बजाय घर पर ही योग करना चाहिए जहां 'आप नहीं जानते कि जिम में प्रशिक्षक कौन है?''

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए पडालकर ने किसी का नाम लिए बिना दावा किया कि ''वे'' (स्पष्ट रूप से दूसरे समुदाय के सदस्यों का संदर्भ देते हुए) महिलाओं को लुभा रहे हैं।

पडालकर ने कहा, हिंदू लड़कियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे ऐसे जिम न जाएं जहां उन्हें पता नहीं होता कि ट्रेनर कौन है। बेहतर होगा कि आप घर पर ही योग करें। आपको नहीं पता कि यह कितनी बड़ी साजिश है। हिंदू युवतियों से कहें कि उन्हें घर पर ही योग या व्यायाम करना चाहिए। उन्हें प्रशिक्षण के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है।

प्रियंक खरगे को धमकी देने वाले व्यक्ति को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु पुलिस ने महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने कथित तौर पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे को फोन किया था और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या को पत्र लिखने को लेकर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कीं। इस आरोपी ने जब खरगे को फोन किया था तब मंत्री ने इस बातचीत का वीडियो बना लिया। उसके बाद सदाशिवनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।

'बेंगलूरु सेंट्रल डिवीजन' और कलबुर्गी पुलिस के संयुक्त अभियान में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी की पहचान धनेश नरोने उर्फ दानप्पा नरोने के रूप में हुई है, जो महाराष्ट्र के सोलापुर का रहने वाला है। सोलापुर कर्नाटक की सीमा से लगा हुआ एक जिला है। खरगे को फोन पर गालियां देने के बाद आरोपी अपने शहर से भागकर लातूर में छिप गया था। लेकिन बेंगलूरु और कलबुर्गी की पुलिस टीम ने उसका पता लगाया, उसे गिरफ्तार किया और बेंगलूरु ले आई।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि धनेश बिस्कुट और कन्फेक्शनरी बनाने वाली कंपनियों के लिए मार्केटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है।

उसने एक सर्च इंजन की मदद से खरगे का फ़ोन नंबर हासिल किया था। बेंगलूरु पुलिस धनेश के पिछले रिकॉर्ड और ऐसे अपराधों में उसकी संलिप्तता की जांच के लिए पूछताछ कर रही है। खरगे ने बुधवार को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कथित तौर पर धनेश द्वारा की गई कॉल शामिल है। आरोपी ने मंत्री को उनके उस पत्र के लिए गाली दी जिसमें उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की थी। मंत्री ने 'एक्स' पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति फोन कॉल पर उन्हें गालियां और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा है। सिद्दरामय्या ने कहा कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, जबकि राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। भाजपा ने खरगे के इस रुख की कड़ी आलोचना की और उन्हें राज्य में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती भी दी।

मंत्री ने हाल में सिद्दरामय्या को एक पत्र लिखकर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था।

हेब्बाल में भी हुई है वोटों की चोरी!

- क्षेत्र के विधायक और शहरी विकास मंत्री ने दी विस्फोटक जानकारी
- 20 हज़ार से ज़्यादा वोट चोरी हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहरी विकास मंत्री बैराती सुरेश, जो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, ने विस्फोटक जानकारी दी है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों में बेंगलूरु शहर के हेब्बाल निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की चोरी हुई है। मंत्री ने यह गंभीर आरोप गुरुवार को हेब्बाल निर्वाचन क्षेत्र के आर.टी. नगर में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा वोट चोरी के खिलाफ आयोजित हस्ताक्षर संग्रह अभियान में लगाया। पिछले विधानसभा चुनावों में हेब्बाल में 20 हज़ार से ज़्यादा वोट चोरी हुए थे। हालाँकि, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और मतदाताओं ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे 32 हज़ार से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत दिलाई। मैं उनका आभारी हूँ।

लोकतंत्र में सभी को एक बार ही वोट देने का अधिकार दिया जाता है। भाजपा उस एक वोट को छीनने की कोशिश करती रही है। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि इसके ज़रिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान हज़ारों लोग आते हैं, जबकि वे हमारे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहते। वे बेंगलूरु के बाहरी इलाके से यहाँ आते हैं और वोट देते हैं। वे अगले चुनावों में फिर आएंगे।उन्होंने आगे कहा कि गंगेनहल्ली वार्ड के एक पते वाले एक हज़ार से ज़्यादा लोग वोट देने आते हैं। यह कैसे संभव है?

उन्होंने कहा कि भाजपा जातियों और धर्मों के बीच नफ़रत के बीज बोकर देश और राज्यों को बाँटने का काम करती रही है। इस पार्टी को मंदिर-मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं सूझ रहा। उस पार्टी का कोई भी नेता देश और राज्य के विकास की बात नहीं करता। इसके बजाय, बैराती सुरेश ने उन पर नफ़रत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि गरीबों, दलितों और कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाने वाली पार्टी कांग्रेस है। केवल हमारी पार्टी ही देश और राज्य का निर्माण कर सकती है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि हर जगह इस तरह के वोट डाले जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और हेब्बाल निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को सावधान रहना चाहिए। मतदाताओं को मामलों की पहचान करने और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करना चाहिए। आगामी दिनों में ग्रेटर बेंगलूरु प्राधिकरण के नगर निगमों के चुनाव होने हैं, इसलिए उन्होंने मतदाता सूचियों की पूरी सावधानी से जाँच करने और मतदान को रोकने का आह्वान किया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया।

जम्मू-कश्मीर के मुद्दों का समाधान राज्य का दर्जा बहाल करने में निहित है: उमर अब्दुल्ला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में ही जम्मू-कश्मीर के सभी मुद्दों का समाधान निहित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से किए गए राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी अपने वादे को पूरा करने का अनुरोध किया।

नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) सरकार का बृहस्पतिवार को एक वर्ष पूरा होने पर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास के लिए अपने प्रयास जारी रखने और पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने का संकल्प लिया।

अब्दुल्ला ने कहा, हमें उम्मीद थी कि केंद्र हमारी सरकार के पहले साल में (जम्मू-कश्मीर को) राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मोदी सरकार से संसद और उच्चतम न्यायालय में केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से किए गए वादे को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, किसी केंद्र शासित प्रदेश में सरकार का नेतृत्व करना एक अलग अनुभव होता है। हमें उम्मीद थी कि केंद्र राज्य का दर्जा देने का अपना वादा पूरा करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हम अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटेंगे।

अब्दुल्ला ने यहां नेकां मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, हमारा अब भी मानना है कि जम्मू-कश्मीर के समक्ष सभी समस्याओं का समाधान राज्य का दर्जा बहाल करने में निहित है।

प्रधानमंत्री से राज्य का दर्जा देने संबंधी वादा पूरा करने का आग्रह करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, एक बार फिर, मैं भारत सरकार,

प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम से आग्रह करना चाहूंगा कि वे जम्मू-कश्मीर के लोगों से किया गया वादा पूरा करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने एक वर्ष पहले सरकार की बागडोर संभाली थी और विकास कार्यों में तेजी लाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने शुरुआत कर दी है। चाहे वह जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे पर विधानसभा में प्रस्ताव लाने का जनता से किया गया राजनीतिक वादा हो, या राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित कराना हो – हमने दोनों काम किए। नेकां सरकार का एक साल का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करने की विपक्षी दलों की मांग का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जब उनकी पार्टी ने लोगों से वोट मांगे थे, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार सिर्फ छह महीने या एक साल तक नहीं, बल्कि पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने विधानसभा में कहा था, यदि आपको हमारे घोषणापत्र के आधार पर हमारा मूल्यांकन करना है तो ऐसा सरकार के पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद कीजिए, क्योंकि कोई भी सरकार छह महीने या एक वर्ष में अपने सभी वादे पूरे नहीं करती है। उन्होंने कहा कि नेकां सरकार लोगों से किए गए वादों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वह पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी।

कर्नाटक ने सट्टेबाजी से संबंधित धनशोधन मामले में कांग्रेस विधायक की ईडी गिरफ्तारी पर लगायी मुहर

बेंगलूरु/नई दिल्ली। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सट्टेबाजी से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी द्वारा चित्रदुर्ग के कांग्रेस विधायक के सी वीरेंद्र की गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने वीरेंद्र (50) की पत्नी की एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने एजेंसी द्वारा वीरेंद्र को गिरफ्तार किये जाने को अवैध और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने का अनुरोध किया था। ईडी ने कांग्रेस विधायक को अगस्त में सिक्किम से गिरफ्तार किया था, जहां वह एक कसीनो किराए पर लेने के लिए व्यावसायिक यात्रा पर गए थे। वीरेंद्र फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

कांग्रेस विधायक की पत्नी आर डी चैत्रा ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में कहा था कि वीरेंद्र के खिलाफ दर्ज सभी पुलिस प्राथमिकी बंद कर दी गई हैं या उनमें छेड़छाड़ की गयी है और केवल एक शिकायत (संख्या 218/2022) लंबित है। उन्होंने कहा कि यह शिकायत भी 30,000 रुपये के विवाद से संबंधित थी, जिसे दिवानी मामला माना गया है तथा ईडी के अनुसार जांच एजेंसी (पुलिस) द्वारा 'बी' रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) दायर की गई।

ईडी ने विधायक पर कई पुलिस प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था, जिनमें अवैध ऑनलाइन/ऑफलाइन सट्टेबाजी और जुए के जरिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। एजेंसी का दावा है कि वीरेंद्र और उनके साथी फोनपैसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ' जैसे भुगतान मंच का इस्तेमाल कर किंग567' जैसा अवैध सट्टेबाजी मंच चलाते थे।

वीरेंद्र की पत्नी ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय को बताया कि उनके पति के खिलाफ फोनपैसा या सट्टेबाजी से कोई सीधा संबंध या आरोप नहीं हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अधिकार क्षेत्र से बाहर है और पीएमएलए की धारा 19 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है।

ईडी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पीएमएलए (धन शोधन रोकथाम अधिनियम) के तहत पूर्व शर्त को पूरा करने वाले अपराध का अस्तित्व है, क्योंकि धन शोधन निरोधक कानून के तहत कार्यवाही तब तक जारी रह सकती है जब तक कि 'बी' रिपोर्ट न्यायिक रूप से स्वीकार नहीं कर ली जाती। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के पास 'पर्याप्त' सामग्री मौजूद है, जो यह मानने के लिए पर्याप्त कारण देती है कि याचिकाकर्ता का पति पीएमएलए, 2002 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि तदनुसार, उक्त रिट याचिका खारिज की जाती है तथा जमानत याचिका दायर करने की छूट दी जाती है।

सर्वेक्षण

बेंगलूरु में गुरुवार को आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण के लिए कावेरी स्थित अपने आवास पर पहुंचे कर्मचारियों के साथ जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या।

नियुक्ति

बेंगलूरु में गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल थावरचन्द गहलोत ने डॉ. रिचर्ड विंसेंट डिसूजा, बी. वेंकट सिंह और डॉ. महेश वाल्वेकर को पद की शपथ दिलाई, जिन्हें कर्नाटक राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नव नियुक्त किया गया है।

डिजिटल रूप में भी पढ़ें दक्षिण भारत हिन्दी दैनिक www.dakshinbharat.com

दिवाली से पहले सोने में उछाल; आभूषण के बजाय छड़, सिक्के खरीद रहे हैं ग्राहक

मुंबई/भाषा। व्यापारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिवाली और शादी के मौसम से पहले सोने की कीमतें अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर हैं, लेकिन इससे उपभोक्ता मांग में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि, कई लोग आभूषणों की बजाय ''ठोस सर्राफा'' को तरजीह दे रहे हैं।एमसीएक्स में दिन में सोने की कीमत 1,28,395 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। मुंबई के प्रसिद्ध झावेरी बाजार में उम्मेदलाल तिलोकचंद झावेरी ज्वेलर्स के मालिक वृषांक जैन ने कहा, सोने की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं और लोग इस पर नज़र रख रहे हैं और निवेश के लिए आ रहे हैं। आभूषणों की मांग धीमी हुई है, लेकिन लोग सोने की छड़ें और सिक्के खरीद रहे हैं। इस त्योहारी मौसम और शादी के मौसम से पहले हम सोने और चांदी की छड़ों की काफी मांग देख रहे हैं। उन्होंने पीटीआई-वीडियो को बताया, कई खरीदार अग्रिम बुकिंग या सोने के सिक्के खरीदकर मौजूदा कीमतों पर ही खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और तेज़ी आने की उम्मीद है। जैन ने कहा कि उपभोक्ता अक्सर सोने को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखते हैं और भारत में इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है क्योंकि धनतेरस जैसे त्योहारों और शादियों जैसे अवसरों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। झावेरी बाज़ार में आए एक ग्राहक देवरस भाई परमार ने जैन की बात से सहमति जताई। परमार ने कहा, दिवाली के दौरान सोना खरीदना शुभ माना जाता है और यह एक निवेश है। आपात स्थिति में हम सोने के बदले नकद प्राप्त कर सकते हैं... मेरे परिवार में हर दिवाली पर सोना खरीदने की परंपरा रही है। भारतीय सर्राफा आभूषण संघ के प्रवक्ता कुमार जैन ने 'ठोस सर्राफा' खरीदने के चलन की पुष्टि की। उन्होंने आगे कहा, शादियों के लिए लोग अपने पुराने सोने को पुनचक्रण करवाने आ रहे हैं और मांग में कोई कमी नहीं आई है।

सोमन्ना ने तिम्माराजनहल्ली-उरुकेरे खंड का निरीक्षण किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तुमकुरु। रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने गुरुवार को तुमकुरु-दावणगेरे नई रेलवे लाइन परियोजना के हिस्से में 13 किलोमीटर के तिम्माराजनहल्ली-उरुकेरे नई लाइन और तुमकुरु-रायदुर्गा नई रेलवे लाइन परियोजना के हिस्से में 12 किलोमीटर के उरुकेरे- तुमकुरु खंड का मोटर ट्रॉली निरीक्षण किया।

मीडिया से बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में, लगभग 11,800 करोड़ की नौ प्रमुख नई रेलवे लाइन परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा निरीक्षण और प्राधिकरण के बाद, तुमकुरु-उरुकेरे-तिम्माराजनहल्ली खंड में ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि वे 17 अक्टूबर को तुमकुरु-रायदुर्गा नई लाइन परियोजना के अंतर्गत आने वाले दोड्डाहल्ली-पावगड़ा-मदकासिरा खंड का निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण में तुमकुरु ग्रामीण के विधायक बी. सुरेश गौड़ा, तुमकुरु शहर के विधायक जी.बी. ज्योति गणेश और निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता प्रसाद और बेंगलूरु मंडल के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने आरएसएस की गतिविधियों को रोकने के लिए नियम लाने का फैसला किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नियम बनाने का निर्णय लिया। इन गतिविधियों में सड़कों पर मार्च करना और सार्वजनिक स्थानों तथा सरकारी परिसरों में कार्यक्रम आयोजित करना भी शामिल है। आरएसएस का नाम लिये बिना कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने संवाददाताओं से कहा, ''हम किसी संगठन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अब से आप सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर जो चाहे नहीं कर सकते। आपको जो भी करना है, वह सरकार की अनुमति लेने के बाद ही करना होगा।''

यह निर्णय राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री खरगे द्वारा मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या को लिखे गए एक पत्र के आधार पर लिया गया, जिसमें उन्होंने आरएसएस और उससे संबद्ध संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। प्रियंक खरगे ने कहा कि यह सरकार पर निर्भर करेगा कि वह ऐसी गतिविधियों को अनुमति देती है या नहीं।

मंत्री ने कहा कि अनुमति देने के लिए कुछ मानक हैं। उन्होंने कहा, ''आप केवल अधिकारियों को सूचना देकर सड़क पर लाठी लहराते हुए नहीं चल सकते या पथ संचलन नहीं कर सकते। ये सभी चीजें हमारे द्वारा लागू किए जाने वाले नियमों का हिस्सा होंगी।'' मंत्री खरगे को हाल के दिनों में कथित तौर पर आरएसएस कार्यकर्ताओं से जान से मारने की धमकियां मिली हैं।

प्रियंक खरगे ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, ''हम जो नियम लाना चाहते हैं, वे सार्वजनिक स्थानों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी परिसरों, सरकारी संस्थानों और सहायता प्राप्त संस्थानों से संबंधित हैं।''

उन्होंने कहा, ''हम गृह विभाग, विधि विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा जारी पिछले आदेशों को एक साथ लाकर एक नया नियम तैयार करेंगे। अगले दो-तीन दिनों में, कानून और संविधान के दायरे में नया नियम लागू हो जाएगा।'' मंत्री ने हाल ही में सिद्दरामय्या को पत्र लिखकर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नामक एक संगठन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सार्वजनिक मैदानों में भी अपनी शाखाएं चला रहा है, जहां नारे लगाए जाते हैं और बच्चों व युवाओं के मन में नकारात्मक विचार भरे जाते हैं।

कैबिनेट ने 117 किलोमीटर लंबे बेंगलूरु बिजनेस कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है : डीके शिवकुमार

- परियोजना 2 साल में पूरी होगी
- भूमि मालिकों के लिए मुआवज़े के चार विकल्प
- किसी भी कीमत पर अधिसूचना रद्द नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को बताया कि कैबिनेट ने 117 किलोमीटर लंबे बेंगलूरु बिजनेस कॉरिडोर को मंज़ूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पूर्ववर्ती पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना का नाम बदलकर बेंगलूरु बिजनेस कॉरिडोर कर दिया गया है और इसे मंज़ूरी मिल गई है। सरकार इतनी बड़ी सड़क परियोजना की घोषणा करके इतिहास को फिर से लिख रही है। भूमि मालिकों को मुआवज़े के चार विकल्प दिए गए हैं।

उन्होंने कहा, यह कॉरिडोर सड़क परियोजना तुमकुरु रोड को येलहंका, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और मैसूरु रोड होते हुए तुमकुरु रोड से जोड़ेगी। इस सड़क का 73 किलोमीटर हिस्सा उत्तरी बेंगलूरु में और बाकी दक्षिणी बेंगलूरु में होगा। उन्होंने आगे कहा, पिछली सरकार ने इस परियोजना को अधिसूचित तो किया था, लेकिन वापस नहीं लिया था। बेंगलूरु को नाइस रोड के विकल्प की ज़रूरत है। हमने हुडको के माध्यम से इस परियोजना के लिए 27,000 करोड़ रुपये का ऋण लेने का फैसला किया है।

शुरुआती अधिसूचना 100 मीटर चौड़ी सड़क के लिए थी, लेकिन हमने सड़क की चौड़ाई 65 मीटर रखने का फैसला किया है, जो बेंगलूरु-मैसूरु राजमार्ग जितनी चौड़ी है। भविष्य में मेट्रो परियोजना के लिए इसमें 5 मीटर की चौड़ाई का प्रावधान होगा। शेष 35 मीटर ज़मीन किसानों को मुआवज़े के तौर पर वापस कर दी जाएगी।

मुआवज़े के चार विकल्प

ज़मीन मालिकों को मुआवज़े के चार विकल्प दिए जा रहे हैं। बाज़ार मूल्य से दोगुना मुआवज़ा देने का प्रावधान है। अगर कुछ ज़मीन मालिक व्यावसायिक ज़मीन नहीं चाहते, तो हम उन्हें बीडीए लेआउट में 40 प्रतिशत विकास भूमि उपलब्ध कराएँगे।

परियोजना 2 साल में पूरी होगी

यह परियोजना 2 साल में पूरी हो जाएगी। अगर कुछ ज़मीन मालिक ज़मीन देने से इनकार करते हैं, तो हम मुआवज़े की राशि अदालत में ज़मानत के तौर पर जमा करेंगे और परियोजना को आगे बढ़ाएँगे। किसी भी कीमत पर किसी भी ज़मीन को डी-नोटिफाई नहीं किया जाएगा। बेंगलूरु में बढ़ते ट्रैफ़िक की वजह से दम घुट रहा है, इसलिए सरकार ने यह ऐतिहासिक फ़ैसला लिया है।

यह पूछे जाने पर कि इस परियोजना की लागत कितनी होगी, उन्होंने कहा, परियोजना का मूल अनुमान 27,000 करोड़ रुपये था। अब चूँकि ज़्यादा किसान ज़मीन के मुआवज़े का विकल्प चुन रहे हैं, इसलिए इस परियोजना की लागत 10,000 करोड़ रुपये से कम होने की संभावना है।

यह पूछे जाने पर कि इस परियोजना से ट्रैफ़िक को कैसे मदद मिलेगी, उन्होंने कहा, हमें ट्रैफ़िक में 40 प्रतिशत की कमी की उम्मीद है क्योंकि आने-जाने वाले वाहन शहर से गुज़रने के बजाय इसी सड़क का इस्तेमाल करेंगे।

यह पूछे जाने पर कि प्रस्तावित टोल कितना होगा, उन्होंने कहा, मैं अभी इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। यह एक तकनीकी पहलू है और हम इसे बाद में साझा करेंगे। कोई भी सड़क बिना टोल के नहीं चल सकती। यह पूछे जाने पर कि क्या किसान मुआवज़े के कई विकल्प चुन सकते हैं, उन्होंने कहा, 20 गुंटा से कम ज़मीन वालों को केवल नकद मुआवज़ा दिया जाएगा। इससे ज़्यादा ज़मीन वालों को चुनने के विकल्प दिए गए हैं।

यह पूछे जाने पर कि यह परियोजना दो दशकों से धूल फांक रही है, उन्होंने कहा, पिछली सरकारों में कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी। मैंने एल.के. अतीक को यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी दी थी कि परियोजना जल्द पूरी हो। कुमारस्वामी के इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि बी खाता से ए खाता में बदलाव की पहल में 15,000 करोड़ रुपये हड़पने की साज़िश थी, उन्होंने कहा, उनके लिए अच्छा है, उन्हें अपनी जाँच टीम तैनात करने दीजिए।

कर्नाटक मसौदा विधेयक में बिना लिखित करार के घरेलू कामगारों को काम पर रखने पर रोक

बेंगलूरु। राज्य श्रम विभाग द्वारा तैयार कर्नाटक घरेलू कामगार (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) मसौदा विधेयक में बिना करार के घरेलू कामगारों को काम पर रखने पर रोक लगाई गई है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य किया गया है। मसौदा विधेयक के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं या सेवा प्रदाताओं या एजेंसियों को अधिकतम तीन महीने की जेल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। यह मसौदा विधेयक बुधवार को प्रकाशित किया गया। नागरिकों को सुझाव देने और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। मसौदा विधेयक के अनुसार, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच लिखित करार के बिना किसी भी घरेलू कर्मचारी को नियोजित नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इस तरह के समझौते में नियमों के तहत निर्धारित मॉडल रोजगार समझौते में निर्धारित न्यूनतम श्रम मानकों का पालन किया जाएगा। मॉडल रोजगार समझौते में श्रमिक का नाम और अन्य विवरण, उसे सौंपे गए कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटे, मजदूरी और अन्य लाभ जिनके लिए श्रमिक हकदार है, का उल्लेख किया जाएगा, जिसमें कल्याण शुल्क और अन्य योगदान शामिल हैं।

एचएमटी के पुनरुद्धार के लिए डीपीआर पर काम जारी : कुमारस्वामी

मंड्या। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रतिष्ठित एचएमटी फैक्टरी का पुनरुद्धार करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कुमारस्वामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एचएमटी और भद्रावती स्थित सर एम. विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसएल) का पुनरुद्धार करने के लिए प्रयास जारी हैं।

दक्षिण पश्चिम रेलवे

प्रपत्र 10-01
भारतीय रेलवे
सार्वजनिक अधिसूचना

यह सूचित किया जाता है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधीन नीचे वर्णित क्षेत्र में स्थित रेलवे लाइनों और परिसरों के सभी उपयोग कर्ताओं को ज्ञान हो कि 25,000 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसी सिंगल फे ज ओवरहेट ट्रैक्शन तार निर्दिष्ट तिथि या उसके बाद विद्युतीकृत किए जाएंगे। उक्त तिथि से ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन को हमेशा जीवित (लाइव) माना जाएगा, और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति मैसूरु यार्ड स्टेब्लिंग लाइन 1, 2, 3 और 4 तक उक्त ओवरहेड लाइन के निकट न जाए तथा उसके आसपास कोई कार्य न करे।

क्र. सं.	अनुभाग	किमी में. चैनेज		ऊर्जाकरण की संभावित तिथि
1	मैसूरु यार्ड स्टेब्लिंग लाइन 1, 2, 3 और 4	136/419	137/292	13.10.2025

स्थानः बेंगलूरु
उप मुख्य इलेक्ट्रिक इंजीनियर
कर्षण विनियोग-1/निर्माण/बेंगलूरु छावनी
PUB/563/AAMO/PRB/SWR/2025-26

अनारक्षित टिकटों की बुकिंग में आसानी के लिए गूगल प्ले स्टोर से यूटीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड करें
South Western Railway - SWR | SWRRLY | SWRAILWAYHQ | sw_railways

दक्षिण पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना संः 25/2025, दिनांकः 14.10.2025
भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित कार्य के लिए केवल आईआरईपीएस माध्यम से ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैः
निविदा समापन होने का समयः 10:30 बजे

क्र.सं.	निविदा संख्या	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	निविदा तारीख
01	38255002	कैसनब एचएस बोगी कंप्लीट	16 नं.	28.10.2025
02	33251291	फ्लेक्स बॉल केबल - शार्ट (एल-2333 मिमी.)	411 नं.	28.10.2025
03	25251001	एसी पैंटोग्रॉफ टाईप एएम-12 के लिए मेटालाईज़्ड कॉर्बन स्ट्रिप्स	1248 सेट	05.11.2025
04	33251282	एलएचबी एनएसी कोचों आऊटर के लिए सेकेंडरी स्प्रिंग	142 नं.	06.11.2025
05	16251468ए	कांटाक्ट बीम स्प्रिंग एसेम्बली	30 नं.	06.11.2025
		डब्ल्यूडीजी4, डब्ल्यूडीपी4 लोकोमोटीव इंजिन गवर्नर के लिए ओवरहॉलिंग किट	80 सेट	
		उडवार्ड से उडवार्ड के लिए सेरामिक रेसिस्टर	18 नं.	
06	33251401	ब्रेक सिस्टम और डब्ल्यूएसपी के लिए मस्ट चेंज किट का सेट	26 सेट	10.11.2025
07	33251286	हैंड ब्रेक की व्यवस्था के साथ साथ ब्रेक सिलिंडर (पीपीएसीएम 254-130)	31 नं.	12.11.2025
08	30255004	सेल्फ जेनरेशन एसी कोचों के लिए बोगी फ्रेम की व्यवस्था	20 नं.	17.11.2025
09	77251005	पैंट, एनामेल सिंथेटिक ब्लॉक	143740 ली.	18.11.2025
10	75251013	नॉन एसी कोचों के लिए विनाईल कोटेड अपहोल्सटरी	113979 मी.	18.11.2025

सूचना सं. 23/2025 की निविदा संख्या 38251005 के लिए, निविदा खोलने की अंतिम तिथि 13.10.2025 से बदलकर 03.11.2025 कर दी गई है।
सूचना सं. 22/2025 की निविदा संख्या 33255025 के लिए, निविदा खोलने की अंतिम तिथि 13.10.2025 से बदलकर 29.10.2025 कर दी गई है।
विवरण के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in में
PUB/565/AAMO/PRB/SWR/2025-26
प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, हुबली

अनारक्षित टिकटों की बुकिंग में आसानी के लिए गूगल प्ले स्टोर से यूटीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड करें
South Western Railway - SWR | SWRRLY | SWRAILWAYHQ | sw_railways

अग्निवीरों के छटे बैच की पासिंग आउट परेड हुई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। अग्निवीरों का छठा बैच गुरुवार को गर्व और उत्साह के साथ भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट में शामिल हुआ्। 276 अग्निवीरों की परेड के साथ 24 सप्ताह का गहन भर्ती प्रशिक्षण पूरा हो गया। अब इन सैनिकों को विशेष बल इकाइयों में भेजा जाएगा। परेड का निरीक्षण पैराशूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र के कमांडेंट ब्रिगेडियर योगेश शर्मा ने किया। उन्होंने अग्निवीरों को संबोधित किया और 'ईमानदारी, वफ़ादारी, बहादुरी' को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अग्निवीरों की सराहना की और उनके माता-पिता को बधाई दी।

परेड का नेतृत्व अग्निवीर सरत एस नायर ने किया। अग्निवीर ऋषभ कुमार शॉ को सर्वश्रेष्ठ रिक्रूट का गिल मेडल मिला। शारीरिक प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ रिक्रूट के लिए चीमा मेडल और एंड्यूरेंस में सर्वश्रेष्ठ के लिए रणजीत मेडल अग्निवीर शिववीर ने जीता।

फायरिंग और हथियार प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए घाडगे मेडल अग्निवीर राजकुमार एस ने जीता। अग्निवीर सरत एस नायर को ड्रिल में सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर के लिए छेत्री मेडल से सम्मानित किया गया।

ईडी ने बेलेकेरी बंदरगाह के 'अवैध' लौह अयस्क निर्यात मामले में छापेमारी की

नई दिल्ली/बेंगलूरु। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक और हरियाणा में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी कर्नाटक के बेलेकेरी बंदरगाह के माध्यम से कथित अवैध लौह अयस्क निर्यात से संबंधित धनशोधन जांच के तहत की गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बेंगलूरु और होसपेट (विजयनगर जिला) के कम से कम 20 परिसरों के अलावा हरियाणा के गुरुग्राम में भी कुछ परिसरों पर छापेमारी की गई।

उन्होंने बताया कि धनशोधन की जांच इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकी और आरोपपत्रों के बाद शुरू हुई है। यह जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा सीबीआई को बेलेकेरी बंदरगाह से लौह अयस्क के ''अवैध'' निर्यात के मामलों की जांच करने के निर्देश देने के बाद की गई है। ईडी की छापेमारी में एमएसपीएल लिमिटेड (बाल्डोटा ग्रुप), ग्रीनटेक्स माइनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्रीनिवास मिनरल्स ट्रेडिंग कंपनी, अरशद एक्सपोर्ट्स, एसवीएम नेट प्रोजेक्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और अल्फाइन मिनमेटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कंपनियां और प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं। जिन लोगों के यहां छापेमारी की गई, उनसे उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर टिप्पणी के लिए तत्काल संपर्क नहीं किया जा सका। सूत्रों ने बताया कि आरोप है कि आरोपियों ने बिना कर और रॉयल्टी चुकाए अवैध रूप से लौह अयस्क का उत्खनन, खरीद, बिक्री और परिवहन किया। ईडी के एक सूत्र ने कहा, इससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंची।

समझौता

ग्रेटर बेंगलूरु अथॉरिटी (जीबीए) के मुख्य आयुक्त डॉ. महेश्वर राव और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (गेल) के कार्यकारी निदेशक एस.एन. यादव ने बुधवार को विधान सौधा में उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की उपस्थिति में बेंगलूरु में वैज्ञानिक अपशिष्ट उपचार, निपटान और गैस उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया। शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तुषार गिरि नाथ, मुख्य आयुक्त महेश्वर राव, बेंगलूरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के सीईओ करिगौड़ा और अन्य उपस्थित थे।

पागल प्रेमी ने युवती की चाकू से गोद कर की हत्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। गुरुवार को मंत्री मॉल के पीछे की ओर रेलवे लाइन के पास एक युवक ने युवती को चाकू से रेत दिया। श्रीरामपुरम् थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनशंकरी स्थित एक कॉलेज में पढ़ने वाली 20 वर्षीय युवती यामिनी प्रिया श्रीरामपुरम् क्षेत्र में रहती थीं। एक युवक ने उसे प्यार का इजहार किया था जिसे उसने ठुकरा दिया था। गुरुवार को सुबह जब वह कॉलेज की तरफ जा रही थी तो उस प्रेमी युवक विघ्नेश ने युवती पर हमला कर दिया। पहले उसने प्रिया की आंखों में मिर्ची झोंक दी फिर चाकू से तबाड़तोड़ हमला कर दिया। जिससे प्रिया की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं विघ्नेश वहां से फरार हो गया। पुलिस विघ्नेश की तलाश कर रही है।

डिजिटल रूप में भी पढ़ें
दक्षिण भारत हिन्दी दैनिक
www.dakshinbharat.com

भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (निर्माण एवं अनुरक्षण प्रभाग)
इसरो टेलिमेट्रि ट्रैकिंग एवं कमांड नेटवर्क (इस्ट्रैक) प्लांट नं. 12 एवं 13, तीसरा मेन, द्वितीय फेज, पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूरु-560058 फोन : 080-28094182, 4542 फैक्स : 080-28094180

संक्षिप्त ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, समुचित वर्ग के ठेकेदरों से एनआईटी में निम्नलिखित कार्यो के लिए नग दर ई-निविदाएं ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है।

एनआईटी सं :	इस्ट्रैक/सीएमजी/एमएआईएनटी/सी/ईटीएन-70/2025-26 दिनांक 14.10.2025	इस्ट्रैक/सीएमजी/एमएआईएनटी/सी/ईटीएन-73/2025-26 दिनांक 13.10.2025
कार्य का नाम :	एससीसी परिसर, इस्ट्रैक, बेंगलूरु स्थित एमएसए भवन में अभियंताओं के बैठने की जगह का नवीनीकरण (सिविल इंटीरियर कार्य)	लखनऊ, पोर्टब्लेयर, त्रिवेंद्रम, शिलांग, जोधपुर, भोपाल, हासन, एसडीएससी/एसएचएआर स्थित इस्ट्रैक ग्राउंड स्टेशनों के रखरखाव हेतु तकनीकी सेवा सहायता प्रदान करने हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध।
निविदा का अनुमानित मूल्य :	रु. 24.90 लाख	रु. 28.39 लाख
निविदा दस्तावेज विवरण :	ई-निविदा	ई-निविदा
पूरा करने की अवधि :	तीन (03) माह	बारह (12) माह (विभाग के पास कार्य अनुबंध को आगे 24 माह तक बढ़ाने का अधिकार है)
निविदा प्रलेख डाउनलोड करने की अवधि :	17.10.2025 को 14.30 बजे से 31.10.2025 को 16.30 बजे तक	
बोली स्पष्टीकरण :	17.10.2025 को 15.30 बजे से 03.11.2025 को 16.30 बजे तक	
बोली स्पष्टीकरण के जवाब देने की अंतिम तारीख :	04.11.2025 को 16.30 बजे तक	
निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख और समय	06.11.2025 को 14.30 बजे तक	
निविदा खोलने की नियत तारीख और समय	07.11.2025 को 11.30 बजे से	
अग्रदाय रकम जमा (ईएमडी)	रु. 49,800/-	रु. 56,780/-

पात्रता मानदंड और अन्य ब्यौरे के लिए इच्छुक निविदाकार विस्तृत सूचना आमंत्रण निविदा (एनआईटी) देंखे जिसे वेबसाइट www.isro.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली प्रपत्र औप अन्य ब्यौरे वेबसाइट www.tenderwizard.com/ISRO से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
समूह प्रमुख-सीएमजी, इस्ट्रैक

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान

जयपुर में बनेगा आधुनिक एआई डेटा सेंटर : अश्विनी वैष्णव

मोदी के आने के बाद गुलामी की मानसिकता से बाहर आया भारत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी, जयपुर शहर की ओर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत गुरुवार को अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर 54 निराश्रित एवं गरीब घुमंतू परिवारों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहें। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। दो हजार साल भारत आत्मनिर्भर रहा। दो सो से तीन सो साल अंग्रेज आए, लेकिन हमारी गुलामी की मानसिकता 2014 में बाहर आए। जब मोदी पीएम बने। आत्मनिर्भर भारत को नीतियों में परिवर्तन हुए। 2004 में अटल वाजपेई ने यूपीए को सरकार बनी। तब भारत अर्थव्यवस्था में दस वे स्थान पर था। यूपीए 2014 तक सरकार रही। दस वे नंबर पर ही रहे। यूपीए के दस साल भ्रष्टाचार में खराब हो गए।

फिर मजबूत नेतृत्व मोदी का आया, जिसने हमें गुलाम बनाया था उस देश को पछाड़ कर पांचवे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना। यूपीए में रेलवे का बजट 680 करोड़ था राजस्थान का, काम कैसे होता। आज मोदी राजस्था रेलवे को 10 हजार करोड़ दे रहे है। 55 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 11 साल में इतने काम हुए जितने 60 वर्षों में नहीं हुए। 85 स्टेशनों का नवनिर्माण किया जा रहा है। स्टेशन में हमारी संस्कृति का समावेश है। देश में स्टेशन, हाइवे, एयरपोर्ट बन रहे हैं। अभी जापान के रेलवे मिनिस्टर आए, सूरत से मुम्बई रेल में के गया। अंदर बैठते ही पर्दे, टच बटन देखे, कहा कि ऐसा तो हमारी बुलेट ट्रेन में भी नहीं था। पानी का ग्लास रखा, बोतल टेस्ट किया, ड्राइवर के केबिन में भी पानी नहीं हिला। वंदे भारत ट्रेन में पानी तो नहीं हिला, दुनिया को हिला रही है। नमो भारत, अमृत भारत ट्रेन चली। दस साल पहले मोबाइल फोन बाहर से आते थे, अब 90 फीसदी भारत में बन रहे है।

देश में काम आने वाली सब चीजें धीरे धीरे भारत में बनने लगेंगी। 75साल देश आजादी को हुए, किसी ने संकल्प नहीं लिया आत्मनिर्भर भारत बनाने का, मोदी ने लिया। 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट दी। जैसे ही और मजबूती आई जीएसटी में बड़ी छूट दी। जनता को इसके लाभ मिल रहा है। निर्णायक नेतृत्व की तुम्ही ताकत है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 5 हजार नवयुवकों को राजस्थान में इसकी ट्रेनिंग देंगे। आईटी का जमाना है। जयपुर ने भी एक बड़ा हब और डेटा सेंटर बने, इसका प्रयास करेंगे। जल्द जमीन लेकर एआई डेटा सेंटर बनाएंगे।

सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि सभी देश के लोगों से अपील करती हु कि स्वदेशी अपनाए, दिवाली पर वहीं वस्तु खरीदे जो देश में बनी हो। बीजेपी जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में जयपुर प्रभारी और संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम दक, सांसद मंजू शर्मा, मेयर कुसुम यादव, देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना भी मौजूद रहे।

जैसलमेर बस हादसे के बाद बस का ढांचा बनाने वालों के खिलाफ अभियान

जयपुर। जैसलमेर में बस अग्निकांड के बाद राजस्थान परिवहन विभाग ने निर्धारित सुरक्षा और निर्माण मानकों के उल्लंघन की जांच के लिए बस के ढांचा निर्माताओं के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ओ.पी. बुनकर ने कहा कि जैसलमेर बस हादसे के बाद तत्परता और संवेदनशीलता के साथ व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जोधपुर की एक टीम ने अब तक जोधपुर स्थित 'जैनम कोच क्राफ्टर' परिसर में निर्मित 66 बसों को निरीक्षण के लिए जब्त कर लिया है।

जैसलमेर त्रासदी से संबंधित तकनीकी और नियामक खामियों की जांच के लिए बुनकर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है जिसमें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के दो परिवहन अधिकारी और दो इंजीनियर शामिल हैं। यह टीम बुधवार रात जोधपुर पहुंची और घटनास्थल का दौरा करेगी। राज्य सरकार ने घटना का स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) पुणे को भी आमंत्रित किया है। सीआईआरटी टीम के सप्ताहांत में जैसलमेर आने और जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

इस बीच, राज्यव्यापी विशेष निरीक्षण अभियान जारी है, जिसके तहत 'बस बॉडी कोड' मानकों के उल्लंघन के लिए अब तक 53 बस जब्त की जा चुकी हैं। परिवहन विभाग ने सभी परिवहन यूनियन से अपील की है कि वे अपने वाहनों का परिचालन शुरू करने से पहले सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने में पूरा सहयोग करें।

जैसलमेर बस हादसाः मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर बस हादसे में जान गंवाने वालों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके तहत मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर बस हादसे के मृतको के आश्रितों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है तथा उन्हें पूरी मदद देने और घायलों के हरसंभव उपचार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके तहत मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जिन परिवारों में तीन या अधिक लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना में हुई है, उन परिवारों को 25-25 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपये एवं अन्य घायलों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

शर्मा ने मुख्यमंत्री सहायता कोष नियमों में शिथिलता देते हुए यह स्वीकृति प्रदान की है। मंगलवार को दोपहर बाद जोधपुर जा रही एक निजी बस में जैसलमेर से रवाना होने के बमुश्किल दस मिनट बाद आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई और 19 यात्री जिंदा जल गए और 16 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। गंभीर रूप से घायलों में से एक ने मंगलवार रात अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। एक अन्य घायल की बुधवार को मौत हो गई।

जैसलमेर बस हादसे में मृतकों की संख्या 21 हुई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोधपुर। राजस्थान के जैसलमेर में हुए बस हादसे में मृतकों की संख्या बुधवार को बढ़कर 21 हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झुलसे हुए 14 लोगों का अब भी यहां इलाज चल रहा है जिनमें से चार जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। अधिकारियों के अनुसार हादसे में झुलसे आठ साल के बच्चे की जोधपुर के एमजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया,चार घायलों को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार ने कथित लापरवाही के लिए चित्तौड़गढ़ जिला परिवहन कार्यालय के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। प्राथमिक जांच के अनुसार यह निजी स्लीपर बस एक अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ में पंजीकृत हुई थी और उसमें कई बदलाव किए गए थे। उन्होंने बताया कि यह वातानुकूलित एसी बस थी, लेकिन इसे 'नॉन-एसी' के रूप में पंजीकृत किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) के सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नीलाल ने बस का निरीक्षण किया था लेकिन नियमों के विरुद्ध बदलाव (मॉडिफिकेशन) सहित उल्लंघनों को नजरअंदाज कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए, राज्य सरकार ने लापरवाही के लिए चुन्नीलाल और चित्तौड़गढ़ जिला परिवहन अधिकारी सुरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। प्रारंभिक जांच के मुताबिक बस में कोई आपातकालीन निकास नहीं था। आपात स्थिति में खिड़की के कांच को तोड़ने के लिए कोई हथौड़ा नहीं था और एक संकरा गलियारा था जिसमें यात्री फंस गए थे। जैसे ही तारों में आग लगी, स्वचालित दरवाजा की 'लॉक प्रणाली' सक्रिय हो गयी, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। बस के अंदर कई शव एक दूसरे के ऊपर पड़े मिले।

सड़क हादसे में चार दोस्तों की मौत

जयपुर। बालोतरा कस्बे के पास सड़क हादसे में एक एसयूवी गाड़ी में सवार चार दोस्तों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह भीषण हादसा एक एसयूवी के ट्रेलर से टकराने के कारण हुआ। हादसे में एसयूवी कार में आग लग गई और उसमें सवार चार युवकों की जलने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा बालोतरा के सिणधरी क्षेत्र के सड़ा गांव के पास मेगा हाईवे पर हुआ।

गुड़ामालानी तहसील के डाबड़ा गांव के पांच युवक बुधवार देर रात सिणधरी में काम के बाद घर लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार उनकी एसयूवी की सामने से आ रहे ट्रेलर से भिड़ंत हो गई। टक्कर के कारण एसयूवी में आग लग गई और उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहन सिंह (35), शंभू सिंह (20), पंचा राम (22) और प्रकाश (28) के रूप में हुई है। चालक दिलीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया।

अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोटा। राजस्थान के बारां जिले में अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया और बाद में एक रैली निकाली जिसमें पार्टी की राज्य इकाई के शीर्ष नेतृत्व ने भाग लिया। इस सीट के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा को अयोग्य ठहराए जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी। कृषि उपज मंडी मैदान में आयोजित रैली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कई अन्य नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और लोगों से राज्य विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत करने का आग्रह किया। रैली को संबोधित करते हुए भाया ने कहा कि जिन लोगों ने उन पर और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाए और पुलिस में मामले दर्ज कराए, वे अब खुद सलाखों के पीछे हैं। पायलट ने कहा, उपचुनाव का उद्देश्य सरकार बदलना नहीं है, बल्कि यह राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के वादों और प्रतिबद्धताओं को परखने का एक साधन है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दो साल पहले झूठे वादों के जरिए राज्य में सत्ता में आई थी। गहलोत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चित्तौड़गढ़ में दिए गए उस वादे को तोड़ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। गहलोत ने दावा किया, मुख्यमंत्री शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है या कमजोर कर दिया है।

विलायती बबूल के राज्यव्यापी उन्मूलन की तैयारी में सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यभर से विलायती बबूल (प्रोसोपिस जुलिफोरा) के संपूर्ण उन्मूलन के लिए राज्य सरकार ने व्यापक कार्ययोजना की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में आज सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी शामिल रहे।

दिलावर ने जोधपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश से विलायती बबूल के प्रभावी और स्थायी उन्मूलन के लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करना होगा। वन एवं राजस्व विभागों द्वारा एक स्पष्ट एवं पारदर्शी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश के प्रत्येक गांव में अभियान के रूप में विलायती बबूल के उन्मूलन का कार्य निर्बाध रूप से प्रारंभ किया जाएगा।

उन्होंने वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक आदेश शीघ्र जारी किया जाए ताकि इस पौधे की कटाई के लिए बार-बार अनुमति लेने की आवश्यकता समाप्त हो तथा किसी प्रकार की वैधानिक बाधा न उत्पन्न हो। दिलावर ने बताया कि विलायती बबूल एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है, जो प्रदेश की ग्रामीण भूमि, चारागाहों और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। इसकी गहरी जड़ें (लगभग 30 फीट तक) और अत्यधिक जल सोखने की क्षमता (15 मीटर तक) भूजल स्तर में गिरावट और मृदा की उर्वरता में कमी का कारण बन रही हैं। इसके कारण देशी पौधों की प्रजातियाँ भी नष्ट हो रही हैं।

दिलावर ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से एक व्यवस्थित और सक्रिय अभियान के रूप में विलायती बबूल का उन्मूलन करने की दिशा में कार्य करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कटाई के दौरान अन्य उपयोगी वृक्षों को कोई क्षति न पहुंचे। विलायती बबूल के कोयले के परिवहन में आने वाली प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए परिवहन की अनुमति प्रणाली को सरल बनाया जाए। दिलावर ने सुझाव दिया कि इस पौधे के पुनः उगने की प्रवृत्ति को देखते हुए राज्य सरकार को इसके उन्मूलन के लिए तीन से चार वर्ष की दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करनी होगी।

ओटाराम देवासी ने कहा कि यह पौधा हमारे चारागाह, कृषि भूमि, नदियों/नालों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है, जिसे जड़ से खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मनरेगा और स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर चरणबद्ध तरीके से इसका उन्मूलन किया जाए और सभी विभागों और आम जनता के सहयोग से हम जल्द ही विलायती बबूल मुक्त राजस्थान का सपना साकार करेंगे।डॉ. जोगा राम, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग सहित वन, राजस्व, ग्रामीण विकास, जल संसाधन एवं संग्रहण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने सांसद बेनीवाल पर पलटवार किया

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के उस बयान पर बुधवार को पलटवार किया जिसमें जैसलमेर बस हादसे में झुलसे लोगों को हवाई मार्ग से अस्पताल नहीं पहुंचाए जाने पर सवाल उठाया था। बेनीवाल ने सवाल किया था कि राठौड़ की पत्नी को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से लाया जा सकता है तो हादसे के घायलों को क्यों नहीं? राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पत्नी को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से लाए जाने का खर्च पत्नी की कंपनी ने उठाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया। राठौड़ ने बेनीवाल के बयान को 'घटिया' मानसिकता का बताते हुए कहा कि बेनीवाल की संवेदना मर चुकी है।

उन्होंने कहा, जिन लोगों ने कभी बिजली का बिल जमा नहीं करवाया,घर खाली नहीं किया, वही आज हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि एक ओर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा है जिनकी मैं प्रशंसा करूगा जिन्होंने विपक्ष में होने के बावजूद मेरी पत्नी की कुशलक्षेम पूछी। वहीं दूसरी ओर बेनीवाल हैं जो इतनी घटिया मानसिकता के साथ अनर्गल आरोप लगा रहे है।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व सांसद बेनीवाल ने सवाल उठाया कि सैन्य हेलीकॉप्टर उपलब्ध होने के बावजूद गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए हवाई मार्ग से अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया। बेनीवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में सवाल किया, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा पूछना चाहता हूं कि कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ की धर्मपत्नी को बीमार होने पर जब आप उन्हें पाली से जयपुर हेलीकॉप्टर में ला सकते हैं तो आज जैसलमेर के निकट बस में हुई भीषण आगजनी में गंभीर रूप से झुलसे हुए नागरिकों को 'एयरलिफ्ट' करके जोधपुर क्यों नहीं लेकर आए?

बेनीवाल ने लिखा,जैसलमेर में तो सेना के हेलीकॉप्टर/विमान भी थे, आप केंद्र से एवं सैन्य अधिकारियों से बात करके तत्काल झुलसे हुए नागरिकों को हवाई मार्ग से जोधपुर या जयपुर लाते ताकि उनका समय पर उपचार शुरू होता। राठौड़ ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के भावी प्रत्याशी के बारे में कहा कि उपचुनाव में हम जनसेवक मैदान में उतारेंगे, जो जनता की सेवा सेवक बनकर करेगा। उन्होंने कहा,भाजपा का प्रत्याशी जनता की अपेक्षा को पूर्ण करने वाला और जन भावनाओं के अनुरूप होगा।

हर राज्य में भगोड़ों के लिए विशेष जेल बनें, रेड नोटिस के बाद पासपोर्ट रद्द किए जाएं : अमित शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को हर राज्य में भगोड़ों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक विशेष जेल बनाने का सुझाव दिया और कहा कि इंटरपोल के 'रेड नोटिस' का सामना कर रहे भगोड़ों के पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाए ताकि प्रत्यर्पण के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार के दावों को कमजोर किया जा सके और सीमा पार उनकी बेरोकटोक आवाजाही को रोका जा सके।

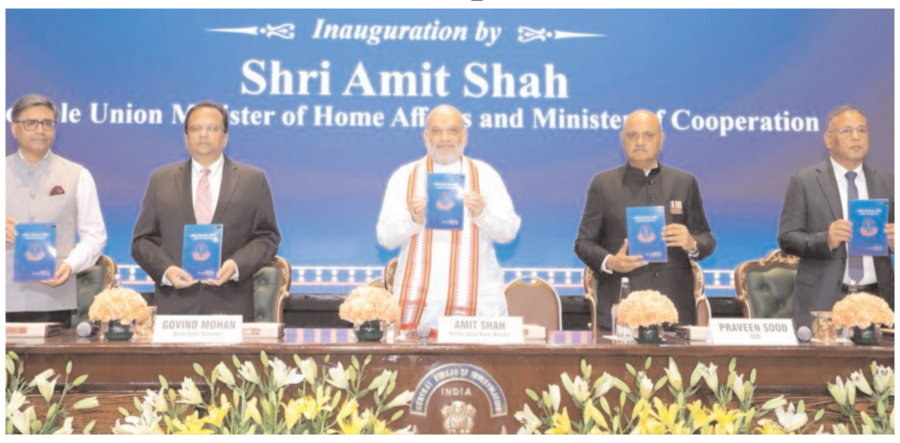

विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी सहित कई भगोड़ों ने विदेशी अदालतों में अपने प्रत्यर्पण का विरोध करने के लिए भारतीय जेलों की 'खराब स्थिति' का मुद्दा उठाया है।

सीबीआई द्वारा आयोजित 'भगोड़ों का प्रत्यर्पण – चुनौतियां और रणनीतियां' विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा, जब तक हम विदेशों से भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारी संप्रभुता और हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले भगोड़ों के मन में भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रति भय पैदा नहीं करते, तब तक हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते।

वित्तीय अपराधों, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी सहित अन्य मामलों में वांछित भगोड़ों को वापस लाने के लिए विभिन्न देशों में भारत के 338 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित हैं।

शाह ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी होने पर उनके पासपोर्ट को निगरानी सूची में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मौजूदा तकनीक के साथ ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब रेड नोटिस जारी होता है, तो भगोड़े की अंतरराष्ट्रीय यात्रा को रोकने के लिए पासपोर्ट रद्द कर दिया जाना चाहिए। अगर हम इस प्रावधान को सिस्टम में शामिल कर सकें, तो इससे भगोड़ों को वापस लाने में मदद मिलेगी।

पूरे देश में एसआईआर कराने का मकसद, वोट चोरी करना है : दिग्विजय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बाराबंकी (उप्र)/भाषा। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे भारत में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का उद्देश्य ''वोट चोरी'' को बढ़ावा देना है, और दावा किया कि 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के घटक दल दस्तावेजी सबूतों के साथ इसका कड़ा विरोध करेंगे।

यहां एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आये सिंह ने संवाददाताओं से कहा, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए निर्वाचन आयोग की मदद से बिहार में एसआईआर की आड़ में 62 लाख वोट कटवाये हैं। भाजपा ऐसा करके लोगों के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, आयोग पूरे भारत में एसआईआर लागू करके वोट चोरी करेगा। 'इंडि' गठबंधन के घटक दल पूरे सबूतों के साथ इसका जमकर विरोध करेंगे।

सिंह ने दावा किया कि भाजपा ने बिहार में आयोग की मदद से 62 लाख वोट भले ही कटवाये हों लेकिन इसके बावजूद वहां 'इंडि' गठबंधन की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 'इंडि' गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और वह भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हराएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग नीतीश सरकार से ऊब चुके हैं।

कांग्रेस ने आरएसएस पर पाबंदी लगाने की मांग की, गृह मंत्री को लिखा पत्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बलिया (उप्र)/भाषा। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर हमेशा से ''देश-विरोधी गतिविधियों'' में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। राय ने बृहस्पतिवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह भी आरोप लगाया कि संघ महात्मा गांधी की हत्या और देश को बांटने के लिए जिम्मेदार है।

राय ने कहा, संघ हमेशा से देश-विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है। महात्मा गांधी की हत्या के पीछे इसी संगठन का हाथ था और इसने देश को बांटने का भी काम किया। यह संगठन गलत कार्यों में शामिल है और उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए।

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर संघ पर पाबंदी लगाने की मांग की है।

केरल में एक युवक की कथित आत्महत्या के मामले का जिक्र करते हुए राय ने आरोप लगाया, 26 साल के संघ प्रशिक्षित आनंदू नाम के एक युवक ने अपने सुसाइड नोट में संघ के वरिष्ठ नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि संघ के अंदर किस तरह का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न होता है।

बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए राय ने दावा किया कि 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) गठबंधन एकजुट है और बिहार में चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और वह सरकार बनाएगा।

राय ने भाजपा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अपने साथियों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा ने हमेशा अपने साथी दलों के साथ खेल खेला है। उसने ओडिशा में बीजू जनता दल को खत्म किया, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गलत किया और अब बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही कर रही है। भाजपा की नीति अपने सहयोगियों को एक-एक करके खत्म करने की है।

भाजपा सरकार ने बिजली व्यवस्था को किया बर्बाद : अखिलेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह चौपट करने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि बिजली निगम खुद अपने ही नियमकायदों की धज्जियां उड़ा रहा है।

यादव ने यहां जारी एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा बिजली व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने की है। उन्होंने कहा, आए दिन बिजली कटौती और बिजली दरों में वृद्धि से लोगों का जीना दूभर हो गया है। 'पावर कारपोरेशन' (बिजली निगम) खुद अपने कायदेकानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। उपभोक्ता को 'प्रीपेड' या 'पोस्टपेड' मीटर चुनने का प्रावधान है, लेकिन विभागीय मनमानी की जा रही है। निगम ने नए कनेक्शन के साथ 'प्रीपेड' मीटर लेना अनिवार्य कर दिया है।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देकर और घरों पर स्मार्ट मीटर लगाकर लूट रही है। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए विद्युत कनेक्शन की लागत पहले जहां एक हजार रुपए थी, अब बढ़कर छह हजार रुपए कर दी गई है। भाजपा सरकार की शह पर बिजली निगम अपने इकतरफा निर्णय थोपने पर आमादा है।

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया, मुनाफाखोरी, कंपनियों से चंदा वसूली और ठेकों में कमीशनखोरी के चलते महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। भाजपा ने ठेले, पटरी वालों से लेकर छोटे दुकानदारों, कारोबारियों और कारखानों तक, सभी के बिजली कनेक्शनों में लूट मचा रखी है।

नीतीश के नेतृत्व में एक बार फिर जीत हासिल करेगा राजग : मोहन यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) एक बार फिर जीत हासिल करेगा। उन्होंने पटना जिले के विक्रम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरभ के समर्थन में एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल तथा कांग्रेस पर भी निशाना भी साधा और कहा कि बिहार की जनता ने जंगलराज देखा है।

सिद्धार्थ सौरभ 2020 में कांग्रेस के टिकट पर विक्रम विधानसभा से चुनाव जीते थे और उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में पिछले दिनों शामिल हुए। भाजपा के टिकट पर बृहस्पतिवार को अपना नामांकन दाखिल किया है।

यादव ने कहा, नीतीश कुमार ने सुशासन के सिद्धांतों से बिहार को विकास की नई गति दी है। बिहार हर काल में अग्रणी रहा है। अवंतिका (उज्जैन) और पाटलिपुत्र का दो हजार साल पुराना रिश्ता है। सम्राट अशोक जब गद्दी संभालने वाले थे, तब वे उज्जैन में थे और यहीं से बिहार लौटे थे।

उनका कहना था, बिहार महात्मा बुद्ध की धरती है। हमारे प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरभ ने जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। बिहार की जनता ने जंगलराज भी देखा है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के शासन में लाइसेंस, कोटा और परमिट राज चलता था। कांग्रेस ने युवाओं की प्रतिभा का गला घोंटा और बिहार को बर्बादी की ओर धकेल दिया। उन्होंने कहा कि बिहार से देश में सबसे अधिक आईएएस अधिकारी निकलते हैं, जो राज्य की प्रतिभा का प्रमाण है।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए उन्होंने कहा, लोकनायक ने लोकतंत्र की रक्षा की थी। हमारी पार्टी और राजग में लोकतंत्र जीवित है, इसलिए यहां एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नीतीश कुमार जी का इतिहास भी यही है।

कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा, लाल किताब वालों को बुद्धि का ह्रास हो गया है। वे न तो भाषा का ध्यान रखते हैं और न ही मर्यादा का। बार-बार उच्चतम न्यायालय में माफी मांगते हैं, लेकिन सुधारते नहीं। कांग्रेस आज भी परिवारवाद की गिरफ्त में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के आर्थिक तंत्र में बड़ा बदलाव आया है।

यादव ने दावा किया, आज गरीबों को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है और दुनिया में भारत की साख बढ़ी है।

कांग्रेस और सपा के चरित्र में 'राजनीतिक ईमानदारी का अभाव': मायावती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चरित्र में 'राजनीतिक ईमानदारी का अभाव' है और केवल बसपा ही हाशिए पर पड़े समुदायों की भलाई और उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए ईमानदारी से समर्पित है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की एक विशेष बैठक को संबोधित करते हुए मायावती ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से 2027 के राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 'राजनीतिक सत्ता की मास्टर कुंजी' हासिल करना और सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति की अपनी विरासत को जारी रखना है।

बयान के मुताबिक, बसपा नेता ने कांशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नौ अक्टूबर को लखनऊ में विशाल राज्य स्तरीय आयोजन की 'ऐतिहासिक सफलता' के लिए उत्तर प्रदेश के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं आदि को हार्दिक बधाई दी।

इस विशाल आयोजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न ट्रेन, निजी बसों, छोटे वाहनों और यहां तक कि पैदल आए लाखों लोगों की ऐतिहासिक भीड़ ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।

मायावती ने कहा, हालांकि, प्रतिद्वंद्वी दलों के नेता, जो आमतौर पर रैलियों के लिए भीड़ इकट्ठा करते हैं, ने यह आरोप लगाकर तुच्छ राजनीति की कि इस आयोजन के लिए सरकारी बसों का इंतजाम किया गया था, जिससे उनकी हताशा जाहिर होती है।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने बसपा की उस लिखित मांग को स्वीकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया जिसमें कहा गया था कि बसपा शासन के दौरान निर्मित और लखनऊ में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित स्मारकों और पार्कों की टिकटों की बिक्री से प्राप्त राजस्व का उपयोग उनके रखरखाव के लिए किया जाए।

मायावती ने कहा, यह बसपा की राजनीतिक ईमानदारी और सद्भावना को दर्शाता है, ऐसे मूल्य जिनकी समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस जैसी पार्टियां कद्र नहीं कर सकतीं क्योंकि राजनीतिक ईमानदारी उनके चरित्र का हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसकी 'जातिवादी मानसिकता' के कारण ही उसने बसपा सरकार के दौरान बनाए गए स्मारकों की उपेक्षा की और बहुजन समुदाय के महान संतों, गुरुओं और समाज सुधारकों के सम्मान में स्थापित कई नए जिलों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों के नाम बदल दिए।

सिलीगुड़ी में बनेगा महाकाल मंदिर : ममता बनर्जी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सिलीगुड़ी में एक विशाल महाकाल मंदिर बनेगा, जिसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा।

दार्जिलिंग में संवाददाताओं से बातचीत में ममता ने कहा कि मंदिर का निर्माण सिलीगुड़ी में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर के बगल में किया जाएगा। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में भगवान शिव का एक नाम महाकाल है।

दार्जिलिंग में महाकाल मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद ममता ने कहा, सिलीगुड़ी में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर के पास एक बड़ा महाकाल मंदिर बनाया जाएगा। इसके लिए एक ट्रस्ट बनाना होगा। ममता को दीघा में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है।

मुख्यमंत्री उत्तर बंगाल में जनसंपर्क कार्यक्रम पर हैं, जहां तेज बारिश और भूस्खलन में भारी नुकसान हुआ था और इस दौरान 32 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि मंदिर के लिए जमीन राज्य सरकार देगी, जबकि मंदिर निर्माण में कुछ समय लगेगा।

बिहार में 'विकास बनाम बुर्के' की शरारत कर रहे हैं कांग्रेस और राजद : योगी आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दानापुर (बिहार)/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को बिहार में महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस तथा उनके अन्य सहयोगी दल मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान करने से संबंधित निर्वाचन आयोग के निर्देशों का विरोध कर विकास बनाम बुर्के'' की नई शरारत कर रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरे आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर 'घुसपैठियों' के जरिये फर्जी मतदान करवाने की मंशा रखने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, बिहार राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के शासन में विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। बिहार की एक विकास को बाधित करने के लिए कांग्रेस, राजद और उनके सहयोगी दलों ने एक नई शरारत शुरू की है। यह विकास बनाम बुर्के की शरारत है।

पटना के बाहरी इलाके दानापुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, क्या फर्जी मतदाताओं को वोट डालने दिया जाना चाहिए? कांग्रेस और राजद यही चाहते हैं, इसलिए बुर्के को लेकर इतना हंगामा मचा रहे हैं। यही कारण है कि वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का भी विरोध करते रहे हैं, क्योंकि वे पुराने बैलेट पेपर के उस दौर को वापस लाना चाहते हैं, जिसमें उनके गुर्गे बूथ लूट सकते थे।

उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद अब सीतामढ़ी का भी कायाकल्प किया जा रहा है। दोनों स्थलों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने पर भी काम चल रहा है।

शुभेंदु ने बंगाल चुनाव में देरी होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होने की चेतावनी दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल)/भाषा। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से सरकार बदलने की बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा।

जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में एक जनसभा के दौरान अधिकारी ने कहा कि अगर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा नहीं हुआ तो चुनाव नहीं होंगे। अधिकारी ने कहा, अगर चार मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की हार होगी और एसआईआर चुनाव से पहले 'सेमीफाइनल' साबित होगा।

अधिकारी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी और भाजपा को मिले वोट के बीच का अंतर केवल 42 लाख है। उन्होंने कहा, मतदाता सूची में अवैध रूप से दर्ज लगभग 2.4 करोड़ नाम हटा दिए जाएंगे।

अधिकारी ने जोर देकर कहा कि अवैध प्रवासियों और अन्य कारणों से पात्र नहीं होने वाले लोगों के नाम एसआईआर के बाद मतदाता सूची में नहीं रहेंगे।

पार्टी के लोकसभा सदस्य खगेन मुर्मू पर हुए हमले के विरोध में भाजपा की रैली का नेतृत्व करने के बाद बैठक में अधिकारी ने कहा, मैं भवानीपुर में ममता (बनर्जी) को हराऊंगा। बनर्जी को 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर अधिकारी ने 1,900 से अधिक मतों से हराया था और इसके बाद बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव में जीत हासिल की थी।

जीवन के अंत तक ओडिशा की सेवा करता रहूंगा : नवीन पटनायक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह जीवन के अंत तक राज्य और यहां के लोगों की सेवा करते रहेंगे। पटनायक ने अपने 79वें जन्मदिन पर पार्टी की वार्षिक 'जन संपर्क पदयात्रा' में शामिल होते हुए यह बात कही।

लगभग छह महीने तक मुंबई और भुवनेश्वर के अस्पतालों में इलाज के बाद पटनायक की यह पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। ठीक होने के बाद उन्होंने लगभग एक महीने तक दिल्ली में आराम किया और पिछले सप्ताह राज्य लौट आए।

ओडिशा के पांच बार मुख्यमंत्री रहे पटनायक ने एकाम्र-भुवनेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नगर पल्ली में मार्च का नेतृत्व किया और बीजद की जन संपर्क पदयात्रा के तहत कुछ कदम चले। पटनायक ने उपस्थित जनसमूह से कहा, मैं हमेशा आपके (ओडिशा के लोगों) साथ हूं, और रहूंगा। मैं जीवन के अंत तक मां ओडिशा की सेवा करता रहूंगा। 'जय जगन्नाथ' के नारे के साथ अपने संक्षिप्त भाषण की शुरुआत करते हुए पटनायक ने बीजद की वार्षिक यात्रा में शामिल होने के लिए कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि बीजद आपकी पार्टी है और ओडिशा के लोगों की पार्टी है।

'उत्कलमणि' गोपबंधु दास की जयंती के अवसर पर नौ अक्टूबर को शुरू हुई जन संपर्क पदयात्रा नौ नवंबर तक जारी रहेगी। एक महीने तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान बीजद भाजपा सरकार की कथित विफलता को उजागर करेगी।

यात्रा में शामिल होने के बाद पटनायक ने खंडगिरी क्षेत्र में 'एसओएस' गांव का दौरा किया और वहां के निवासियों के साथ समय बिताया तथा बच्चों को मिठाइयां बांटीं।

विदेशी लीग में खेलने से भारतीय खिलाड़ियों को अच्छा अनुभव मिलेगा : शास्त्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सिडनी/भाषा। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने अधिक से अधिक भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति देने की वकालत करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने से उन्हें अच्छा अनुभव मिलेगा।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अभी अपनी सक्रिय खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता। भारतीय क्रिकेटर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सहित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने और बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद ही विदेश में खेल सकते हैं।

अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हाल ही में बिग बैश लीग (बीबीएल) में शामिल होने वाले पहले शीर्ष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने आगामी सत्र के लिए सिडनी थंडर के साथ अनुबंध किया है।

शास्त्री ने विलो टॉक पॉडकास्ट पर कहा, भारत एक विशाल देश है। वहां हर किसी को खेलने का मौका नहीं मिलता, हर कोई सफल नहीं हो पाता। अगर कोई खिलाड़ी टेस्ट टीम में जगह नहीं बना सकता, लेवल सी या लेवल डी का अनुबंध नहीं पा सकता, तो उसे बिग बैश लीग में खेलने से क्यों रोका जाए। उन्होंने कहा, इन लीग में खेलने का अनुभव उनके लिए मददगार साबित होगा, जैसे आईपीएल ने कई युवा खिलाड़ियों की मदद की है, क्योंकि वे शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं।

शास्त्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के चोटी के खिलाड़ियों के साथ खेलने और कोचिंग स्टाफ में शामिल पूर्व क्रिकेटरों से भारत के युवा खिलाड़ियों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, वे दबाव को झेलना सीखते हैं।

सुविचार

चिकित्सक की सर्वोच्च पुकार, उसकी एकमात्र पुकार, बीमार लोगों को स्वस्थ बनाना है ठीक करना, जैसा कि इसे कहा जाता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

'तेजस्वी' ट्रंप का भारत 'ज्ञान'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के संबंध में ऐसे तथ्य पेश कर रहे हैं, जिनका हकीकत से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति प्रतीत होते हैं, जिनका भारत के बारे में सामान्य ज्ञान बहुत ज्यादा गलत जानकारियों से भरा हुआ है, लेकिन उसे इस तरह बयान करते हैं, गोया इनसे बड़ा कोई विशेषज्ञ नहीं है। ट्रंप की यह टिप्पणी अत्यंत हास्यास्पद है, 'हर साल आपके (भारत) पास एक नया नेता होता है। कुछ तो कुछ महीनों के लिए (सत्ता में) रहते हैं और यह साल दर साल होता रहा है...।' ट्रंप किस ज़माने की बात कर रहे हैं? नब्बे के दशक में कुछ समस्याएं जरूर आई थीं, लेकिन उसके बाद ऐसा कब हुआ? अमेरिकी राष्ट्रपति को चाहिए कि वे इंटरनेट पर कुछ सर्च ही कर लें। भारत में लोकतंत्र मजबूत है। यहां राजनीतिक स्थिरता है। देश में समय पर चुनाव होते हैं। करोड़ों मतदाता नई सरकार चुनते हैं। वर्ष 2014 से तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले डॉ. मनमोहन सिंह ने एक दशक तक देश का नेतृत्व किया था। हर साल नया प्रधानमंत्री हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जरूर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने पाकिस्तान का इतिहास पढ़ लिया और अब उसे भारत के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मई में यह कहकर खुद के ज्ञान का प्रदर्शन किया था कि 'भारत और पाकिस्तान सदियों से लड़ रहे हैं!' भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है, जबकि पाकिस्तान तो वर्ष 1947 में बना था। उससे पहले पाकिस्तान का कहीं नामो-निशान नहीं था, लेकिन ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि मैंने सदियों पुरानी लड़ाई बंद करवाकर शांति की स्थापना में अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। वे गलत जानकारी देकर नोबेल पुरस्कार के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहते थे।

डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा भी सच्चाई से परे है कि 'अगर भारत (रूस से) तेल नहीं खरीदता है तो रूस-यूक्रेन युद्ध बहुत आसानी से बंद हो जाएगा।' रूस के पास हथियारों का बड़ा भंडार है। लड़ाई लंबी खींचना उसके लिए असंभव नहीं होगा। यह न भूलें कि चीन भी रूस से तेल खरीदता है। अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदता तो कई देशों में ईंधन का संकट पैदा हो सकता था। याद करें, कभी अपने चुनावी भाषणों में ट्रंप यह युद्ध रुकवाने के लिए कितने बड़े दावे करते थे! अब दावे धराशायी हो गए तो भारत पर झूठे आरोप लगाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप जुलाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनॉमी' बता चुके हैं, जबकि कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अपनी रिपोर्टों में अनुमान लगा चुकी हैं कि भारत सबसे ज्यादा तेजी से उन्नति करने वाले देशों में से एक है। इन दिनों जब दीपावली के लिए खरीदारी हो रही है तो कई बाजारों में पांव रखने की जगह नहीं मिल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोरोना महामारी का बहुत मजबूती से मुकाबला किया था और बहुत जल्द अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। ट्रंप के बयान सुनकर लगता नहीं कि ये कभी अखबार पढ़ते होंगे। इनके अतिशयोक्तिपूर्ण दावे उन लोगों को जरूर भ्रमित कर सकते हैं, जो पढ़ने-लिखने से कोसों दूर हैं। जो व्यक्ति देश-दुनिया की सामान्य जानकारी भी रखता है, वह ट्रंप के झूठ को आसानी से पकड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति कभी 100 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, कभी भारत को टैरिफ किंग बताते हैं, तो कभी भारत-पाक संघर्ष विराम कराने का झूठा श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की जितनी किरकिरी ट्रंप ने करवाई है, उतनी शायद ही किसी (पूर्व) राष्ट्रपति ने करवाई होगी। भविष्य में भी इतने 'तेजस्वी' राष्ट्रपति दुर्लभ होंगे।

ट्वीटर टॉक

बालोतरा के सड़ा गांव में ट्रेलर और स्कॉर्पियो के बीच हुई भीषण दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें।

-वसुंधरा राजे

आप सभी को विश्व खाद्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ! आइए, हम सभी मिलकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पोषण स्तर को सुदृढ़ बनाने और भोजन की बर्बादी को रोकने का दृढ़ संकल्प लें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त, पौष्टिक और सुरक्षित आहार उपलब्ध हो सके।

-भजनलाल शर्मा

जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में जैसलमेर बस हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों से मुलाकात की एवं उन्हें हिम्मत बंधाई। यहां मौजूद इन पीड़ित परिजनों ने अपनी व्यथा बताई। पीड़ितों ने उनके सामने आ रही दिक्कतों के बारे में बताया ।

-अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

जीवन का सत्यबोध

एक किसान बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा था। खेती-बाड़ी करता था। बहुत दिनों के बाद उनके घर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम हारू रखा गया। माता-पिता दोनों को उस इकलौते पर अत्यधिक स्नेह था। गांव के सभी लोग किसान का आदर करते थे। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था कि किसी ने आकर बताया 'हारू को हैजा हो गया है।' किसान तुरंत घर लौटा और उसने पूरी लगन से उसका उपचार कराया, परंतु अंततः लड़का चल बसा। सभी लोग शोक में डूब गए, पर किसान शांत रहा। वह सबको समझाने लगा कि शोक करने से कुछ नहीं होता। वह फिर खेत पर काम करने चला गया। लौटकर देखा तो उसकी पत्नी रो रही थी। उसने पति से कहा'तुम बड़े निष्ठुर हो! बेटा चला गया और तुम्हारी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला।' किसान ने शांत स्वर में कारण बताया'कल मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा उसमें मैंने स्वयं को राजा देखा, मेरे आठ पुत्र थे और मैं बहुत सुखी था। तभी मेरी आंख खुल गई। अब सोचता हूं, मैं उन आठ बेटों के लिए रोऊं या इस एक हारू के लिए?' किसान ज्ञानी था, इसलिए वह समझ गया था कि जिस प्रकार स्वप्न की अवस्था मिथ्या होती है, उसी प्रकार जागृति की अवस्था भी अस्थायी है।

सामयिक

संवेदनशीलता से ही रोके जा सकेंगे बाल अपराध

अमित बैजनाथ गर्ग

मोबाइल : 78770 70861

अपनी आन-बान-शान और संस्कृति तथा परंपराओं के लिए अनूठी पहचान रखने वाले राजस्थान में लगभग हर तरह के अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। यह स्थिति चिंताजनक तस्वीर खींच रही है। प्रदेश के अपराध बारबार देश में सुर्खियां बन रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2023 की रपट जारी हुई है। इसमें प्रदेश में कई तरह के अपराधों में इजाफा हुआ है। चाहे महिलाओं पर अपराध हो या फिर बुजुर्गों से अमानवीय व्यवहार, हर क्षेत्र में राजस्थान में अपराध बढ़े हैं। रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान, असम और केरल जैसे राज्यों में बाल अपराधों की श्रेणी के मामलों में चिंताजनक उछाल आया है।

आइए, सबसे पहले राजस्थान में बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों की कुछ घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जयपुर में अप्रैल, 2025 में 13 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या का मामला उजागर हुआ। इसमें बालिका की पहचान छुपाते हुए पुलिस ने दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। वहीं भीलवाड़ा जिले के एक सरकारी स्कूल में 11 वर्षीय छात्रा स्कूल आने के बाद लापता हो गई और बाद में उसका शव मिला। मामले में रेप व हत्या के आरोप में शिक्षक और प्रिंसिपल पर संदेह था। इधर, जून, 2025 में अलवर जिले में 7 वर्षीय बच्चे का अपहरण, फिरौती और बाद में हत्या कर दी गई। अभियुक्त परिवार का ही सदस्य था। सितंबर, 2025 में भरतपुर के सरकारी अस्पताल में दवा घोटाले के चलते दो बच्चों की संदिग्ध मौत। इसके बाद सीकर में भी एक बच्चे की मौत हो गई। एक मौत की घटना और घटी।

एनसीआरबी की रिपोर्ट चौंकाने वाले भयावह आंकड़ों की ओर इशारा करती है। राजस्थान में बाल अपराध के मामले में 2018 से 2022 के बीच, जहां राजस्थान में हर साल औसतन 6,200 मामले दर्ज हुए, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर 10,500 से अधिक हो गई। इस तरह बाल अपराधों में लगभग 70 फीसदी की वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि भारत के औसतन 25 प्रतिशत की दर से कहीं अधिक है। राजस्थान जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक गंभीर संकेत है, लेकिन विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यह केवल अपराध बढ़ने का नहीं, बल्कि रिपोर्टिंग के अधिक सटीक और सक्रिय होने का नतीजा भी हो सकता है। बाल अपराध के मामले में राजस्थान की वृद्धि पुलिस के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींचने के लिए काफी है।

इधर, राजस्थान पुलिस ने प्रदेश में अपराधों को लेकर 202425 के कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं।

पुलिस के अनुसार, जनवरी से जून, 2025 के बीच बाल अपराधों में निरंतर वृद्धि रही है। इनमें पॉक्सो एक्ट के तहत 1,631 मामले दर्ज किए गए। वहीं बाल अपहरण अथवा किडनैपिंग के 500 से अधिक मामले सामने आए। साइबर क्राइम में बच्चों को निशाना बनाने के मामलों में 400 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। केवल 53 मामलों में ही चार्जशीट दाखिल हुई। इनमें 186 केस फर्जी निकले। 700 से अधिक मामलों की जांच अभी लंबित चल रही है। इन आंकड़ों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रदेश में जहां एक ओर बाल अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं पुलिस की कार्यशैली बहुत कमजोर नजर आ रही है। पुलिस को इस दिशा में सोचने और तेजी से कार्य करने की सख्त जरूरत है। अब बात करते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट की। रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में बच्चों के खिलाफ अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान, असम और केरल जैसे राज्यों में इस श्रेणी के मामलों में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज हुआ है। 2023 में बच्चों के अपहरण के मामलों का हिस्सा कुल बाल अपराधों में 54 फीसदी से ज्यादा रहा। अक्सर ये मामले पारिवारिक विवाद, नाबालिग लड़कियों को प्रेमप्रसंग के बहाने ले जाना या बाल श्रम से जुड़े रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य में हर दो में से एक मामला बच्चों के अपहरण से जुड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि बाल अपराधों के मामले में राजस्थान सबसे आगे रहा है। यह गंभीर संकेत है, जिसे समय रहते समझने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो आगे परिणाम और भी चिंताजनक रहेंगे।

बाल अपराधों को रोकने की दिशा में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य में बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में वृद्धि चिंताजनक है। साल 2018 से 2023 तक बच्चों के साथ होने वाली हिंसा के मामले दोगुने से भी अधिक हो गए हैं। बच्चों के साथ होने वाली हिंसा के बढ़ने का प्रमुख कारण बच्चों का सोशल मीडिया के साथ उनकी पहुंच का बढ़ना है। दूसरा मुख्य साथ परिवारों में बढ़ती आपसी हिंसा और अलग होकर एकल परिवार होना है। असल में यह सवाल नीतिगत विमर्श का केंद्र है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों में दर्ज मामलों की बढ़ोतरी का अर्थ हमेशा अपराधों में बढ़ोतरी नहीं होती। पुलिस रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल में सुधार, पॉक्सो जैसे कानूनों की सख्त लागू व्यवस्था और जागरुकता अभियानों से भी आंकड़े ऊपर जा सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि समाज अब ऐसे मामलों को दबाने के बजाय रिपोर्ट करने की ओर झुक रहा है, जो एक सकारात्मक संकेत है।

अब बात करते हैं पॉक्सो कानून की। इस कानून ने रिपोर्टिंग की तस्वीर बदल दी है। राजस्थान में यौन अपराधों यानी कि पॉक्सो एक्ट से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मामलों के वर्गीकरण में बड़ा बदलाव हुआ है। 2018 से पहले कई मामले भारतीय दंड संहिता की सामान्य धारा 376 (बलात्कार) के तहत दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब इन्हें सही श्रेणी यानी कि पॉक्सो की धाराओं 4 और 6 में दर्ज किया जा रहा है। इस बदलाव ने न केवल कानूनी स्पष्टता बढ़ाई है, बल्कि बच्चों से जुड़े अपराधों की वास्तविक तस्वीर भी सामने आई है। 2022 में जहां ऐसे मामलों की संख्या लगभग 2,700 थी, वहीं 2023 में यह बढ़कर 3,500 से अधिक हो गई। यह दर लगातार तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं समाधानों की। राजस्थान सरकार ने बाल अपराधों के समाधान के लिए बाल संरक्षण इकाइयों को मजबूत करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाने और साइबर सुरक्षा इकाइयों को संवेदनशील बनाने की दिशा में काम शुरू किया है। इसके अलावा पुलिस को भी इस दिशा में तेजी से कार्य करने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। वहीं सामाजिक और गैर सरकारी संगठन भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरुकता अभियान चला रहे हैं। फिर भी इन प्रयासों को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इसलिए जरूरत है सोच बदलने और जागरूक होने की। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कानून की अपेक्षा सामाजिक सोच में बदलाव से ही तस्वीर बदल सकती है, जिसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। बाल अपराध संवेदनशील विषय है, इसे गंभीर होकर ही समझा और रोका जा सकता है।

विचार

हिंदी के खिलाफ बिल : तमिलनाडु सरकार को क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?

महेन्द्र तिवारी

मोबाइल : 9989703240

तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन लंबे समय से राज्य की पहचानों और सांस्कृतिक स्वायत्तता का प्रतीक बनकर सामने आया है। हाल के घटनाक्रम में डीएमके नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने राज्य में हिंदी फिल्मों, हिंदी गानों और सार्वजनिक होर्डिंग्स तथा बोर्ड्स पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक नया विधेयक लाने की घोषणा की थी। इस प्रस्तावित बिल ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी बहस और तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनकी सरकार का तर्क था कि यह कदम तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष और कानूनी विश्लेषकों ने इसे संविधान के विरुद्ध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात बताकर विरोध जताया। बिल के मसौदे में यह स्पष्ट किया गया था कि पूरे तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों, सिनेमाघरों, मीडिया, विज्ञापन होर्डिंग्स, और गानों में हिंदी के प्रयोग पर रोक होगी। डीएमके नेताओं का कहना था कि हिंदी का 'थोपना' तिरस्कारपूर्ण और तमिल आत्मसम्मान के विपरीत है। राज्य सरकार ने केंद्र शासन, खासकर भाजपा पर ये आरोप लगाए हैं कि त्रिभाषा फॉर्मूला और नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी को दक्षिण भारत में जबरन लागू किया जा रहा है। इसी साल राज्य बजट के लोगो में भी भारतीय रुपया चिन्ह की जगह तमिल अक्षर रखा गया था, जिसे तमिल पहचान और भाषा सम्मान का प्रतीक बताया गया। हालांकि, सरकार द्वारा घोषणा के तुरंत बाद जबरदस्त राजनीतिक और कानूनी प्रतिक्रिया सामने आई। सरकारी सूत्रों के अनुसार, विधेयक पेश करने से पहले एक आपात कानूनी बैठक हुई, जिसमें तमिलनाडु बार और विभिन्न संवैधानिक विशेषज्ञों के सुझाव लिए गए। कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 343-351 (संघ की भाषाएँ) के तहत असंवैधानिक साबित हो सकता है। विपक्षी बीजेपी और तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि यह कदम सिर्फ राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है और व्यापार, लोकप्रिय संस्कृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक असर डालेगा। भाजपा नेता ने इसे मूर्खतापूर्ण और बेतुका बताया तथा इसे राज्य-स्तरीय भावना भड़काने वाला बताया।

जनता और फिल्मी समुदाय ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक प्रसार माध्यमों पर इसकी आलोचना की। कई लोगों ने तमिलनाडु की भाषा नीति का समर्थन किया, लेकिन हिंदी के पूर्ण बहिष्कार को अनुपयुक्त और संकीर्ण सोच बताया। ऐसा माहौल बना कि तमिल पहचान की रक्षा और भाषाई बहुलता का संतुलन साधना एक मुश्किल राजनीतिक चुनौती है। साथ ही, यह भी आरोप लगे कि डीएमके सरकार यह विवाद ऐसे समय ला रही है जब प्रशासन पर निवेश और रोजगार के कई अहम मसले लंबित हैं। विरोधियों ने इसे ध्यान भटकाने का हथकंडा करार दिया। इन सारे दबावों के बीच सरकार को अपने फैसले की समीक्षा करनी पड़ी। 15 अक्टूबर को प्रस्तावित विधेयक को विधानसभा में रखने से पहले ही स्थगित कर दिया गया। एक बार फिर, सरकार ने बयान दिया कि वह संविधान की सीमा में रहकर ही कोई फैसला लेगी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यापारिक-अधिकारों का सम्मान करेगी। राज्य के वरिष्ठ नेता ने कहा कि डीएमके हिंदी भाषा या उत्तर भारतीय संस्कृति का विरोध नहीं करता, बल्कि उसका विरोध उस प्रक्रिया से है जिसमें एक भाषा को जबरदस्ती थोपने का प्रयास हो। सामाजिक और कानूनी बहस के बाद प्रदेश सरकार ने बिल को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया।

तमिलनाडु की यह घटना भाषाई-सांस्कृतिक संवेदनशीलता, संविधान की रक्षा, कारोबार के व्यापक हित और जनभावना की जटिलता को फिर सामने लाती है। केंद्र सरकार के साथ राज्य का रिश्ता लंबे समय से भाषाई नीतियों के विवाद की वजह से तनावपूर्ण रहा है। दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु ने हिंदी के थोपे जाने का दशकों से विरोध किया है, और यह मुद्दा सिर्फ स्कूलों या कार्यालयों की भाषा तक सीमित नहीं, बल्कि तमिल अस्मिता के रक्षार्थ व्यापक सामाजिक संघर्ष का हिस्सा बन चुका है। वर्तमान दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय पहचान के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सार्वजनिक दबाव, व्यापारिक हित और कानूनी दायरे की टकराहट ने इस बार भी सरकार को कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों के लिए भाषाई मुद्दा न केवल सत्ता की राजनीति का हथियार बना रहा है बल्कि यह क्षेत्रीय अस्मिता के प्रहरी की भूमिका अपना चुका है। विरोधी गुट सरकार के फैसले को 'राजनीतिक स्टंट' बताते हैं, तो समर्थक इसे तमिल स्वाभिमान की रक्षा के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। सरकारी बयान के अनुसार, भविष्य में भी अगर हिंदी को अनिवार्य रूप से थोपने के प्रयास होंगे तो राज्य कानून के दायरे में रहकर कदम उठाएगा। फिलहाल जनता, व्यापारिक समुदाय, फिल्म उद्योग, और राजनीतिक दल इस विषय पर सतर्क हैं। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी विधेयक का स्थगन संविधान, व्यापार और सामाजिक जटिलताओं को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय है, जो आने वाले समय में राज्य की भाषा नीति और केंद्र-राज्य संबंधों की दिशा को भी प्रभावित करेगा।

नजरिया

मुफ्त अनाज सहायता के चक्रव्यूह में फंसी भारत की गरीबी

बाल मुकुन्द ओझा

मोबाइल : 9414441218

हर साल की भांति आज भी यानि 17 अक्टूबर को हम अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाने जा रहे है। इस बीच कई बार गरीब की परिभाषा बदली मगर गरीबी उन्मूलन को पूरी तरह अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। इसके विपरीत भारत ने 80 करोड़ से अधिक की अपनी आबादी को मुफ्त अनाज सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर अपनी सरकार का मंतव्य जाहिर कर दिया। साथ ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा कर दिया। साल दर साल दी जा रही यह खाद्य सहायता कब तक जारी रहेगी, कोई बताने वाला नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने भी गरीबी घटने के भारत के इस दावे को स्वीकार कर लिया। विख्यात कृषि अर्थशास्त्री डॉ. गुलाटी की माने तो, जब देश में अत्यधिक गरीबी सिर्फ 5 प्रतिशत है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन क्यों दिया जा रहा है? क्या वे अपना भोजन खरीदने में सक्षम नहीं हैं। दावों प्रतिदावों के बीच गरीबी के खिलाफ संघर्ष आज भी जारी है। विचारणीय बात तो यह है मुफ्त अनाज का यह मायाजाल कब तक जारी रहेगा और आखिर यह गरीबी कब ख़त्म होगी। पैसा फेंक तमाशा देख के इस चक्रव्यूह से आज़ादी कब मिलेगी।

संयुक्त राष्ट्र की गरीबी के खिलाफ संघर्ष की विभिन्न रिपोर्टों का गहन अध्ययन करें तो पाएंगे आज भी दुनियाभर में लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए जूझ रहे है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र ने अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को मनाने की पहल 22 दिसम्बर 1992 को की थी। यह लोगों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को उजागर करने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का एक वैश्विक मंच है। यह दिन गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के महत्व को उजागर करता है।

दुनिया भर में गरीबी की स्थिति आज भी बेहद चिंताजनक है। विश्व बैंक के मुताबिक लगभग 700 मिलियन लोग आज भी अत्यधिक गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं। रिपोर्ट से साफ़ होता है, दुनिया की एक बड़ी आबादी आज भी बुनियादी आवश्यकताओं, जैसे भोजन, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच नहीं पाई है। हमारे देश की बात करें तो आजादी के 78 सालों के बाद भारत में गरीब और गरीबी पर लगातार अध्ययन और खुलासा हो रहा है। भारत की गरीबी आज भी आंकड़ों के भ्रम जाल में उलझी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सरकार सफल रही है। वहीं 16 करोड़ घरों में नल का पानी पहुंचाया है और गरीब परिवारों के लिए 5 करोड़ घर बनाए हैं। इसके अलावा 12 करोड़ से अधिक शौचालय उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें इन सुविधाओं की कमी के कारण सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती थी।

भारत सरकार ने हर प्रकार की गरीबी को कम करने के लक्ष्य के साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसी उल्लेखनीय पहलों ने स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे वंचित रहने में काफी कमी आई है। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक का संचालन करते हुए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 81.35 करोड़ लाभार्थियों को कवर करती है, जो ग्रामीण और शहरी आबादी को खाद्यान्न प्रदान करती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाना, सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। मातृ स्वास्थ्य का समाधान करने वाले विभिन्न कार्यक्रम, उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन वितरण, सौभाग्य के माध्यम से बिजली कवरेज में सुधार, और स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे परिवर्तनकारी अभियानों ने सामूहिक रूप से लोगों की रहने की स्थिति और समग्र कल्याण की स्थिति में सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जन धन योजना और पीएम आवास योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने वित्तीय समावेशन और वंचितों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में आने वाली मूलभूत समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है ताकि देश एक विकसित राष्ट्र यानी विकसित भारत 2047 बनने की ओर अग्रसर हो सके। सरकारी स्तर पर यदि ईमानदारी से प्रयास किये जाये और जन धन का दुरूपयोग नहीं हो तो भारत शीघ्र गरीबी के अभिशाप से मुक्त हो सकता है।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

प्रदर्शन

तिरुवनंतपुरम में महिला मोर्चा की सदस्य सबरीमाला मंदिर में सोने की परत चढ़ाने में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुईं।

रूस को भारत के साथ ऊर्जा व्यापार जारी रखने का भरोसा : उप प्रधानमंत्री नोवाक

मॉस्को/भाषा। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने बृहस्पतिवार को कहा कि रूस को विश्वास है कि भारत के साथ उसका ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा। नोवाक का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने उन्हें रूस से तेल खरीदना बंद करने का आश्वासन दिया है। स्वतंत्र समाचार एजेंसी 'इंटरफैक्स' ने नोवाक के हवाले से कहा, हम अपने मित्रवत साझेदारों के साथ सहयोग जारी रखेंगे। हमारे ऊर्जा संसाधनों की मांग बनी हुई है। यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य और व्यावहारिक है। नोवाक रूस के ऊर्जा क्षेत्र को भी देखते हैं। उन्होंने कहा, ...मुझे विश्वास है कि हमारे साझेदार हमारे साथ काम करना, बातचीत करना और ऊर्जा सहयोग विकसित करना जारी रखेंगे।

नोवाक ने यह टिप्पणी ट्रंप के इस दावे के जवाब में की कि जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत, रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि यद्यपि भारत खरीद में तत्काल कटौती नहीं कर सकेगा लेकिन ऐसा करना जरूर शुरू कर देगा।नोवाक ने कहा, आज हमें मीडिया में केवल यही सुनने को मिल रहा है कि हमारे साझेदार यह घोषणा कर रहे हैं कि कोई भी उन पर हुक्म नहीं चला सकता और वे अपना रास्ता स्वयं चुनेंगे।ट्रंप के तेल व्यापार संबंधी दावों के जवाब में भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह बाजार की स्थितियों को पूरा करने के लिए अपनी ऊर्जा स्रोतों को '' व्यापक कर रहा है और उसमें विविधता'' ला रहा है।

भारत ने इस बात पर जोर दिया कि उसकी आयात नीतियां पूरी तरह से राष्ट्रीय हित पर आधारित होंगी। पारंपरिक रूप से पश्चिम एशियाई तेल पर निर्भर भारत ने फरवरी, 2022 में रूसी सेना के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस से अपने आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की। पश्चिमी प्रतिबंधों और यूरोपीय मांग में कमी के कारण रूसी तेल भारी छूट पर उपलब्ध हो रहा है। स्वतंत्र समाचार एजेंसी 'इंटरफैक्स' के अनुसार, 2025 के पहले सात महीने में रूसी कच्चे तेल का निर्यात 8.75 करोड़ टन या भारत के कुल आयात का 36.4 प्रतिशत रहा।

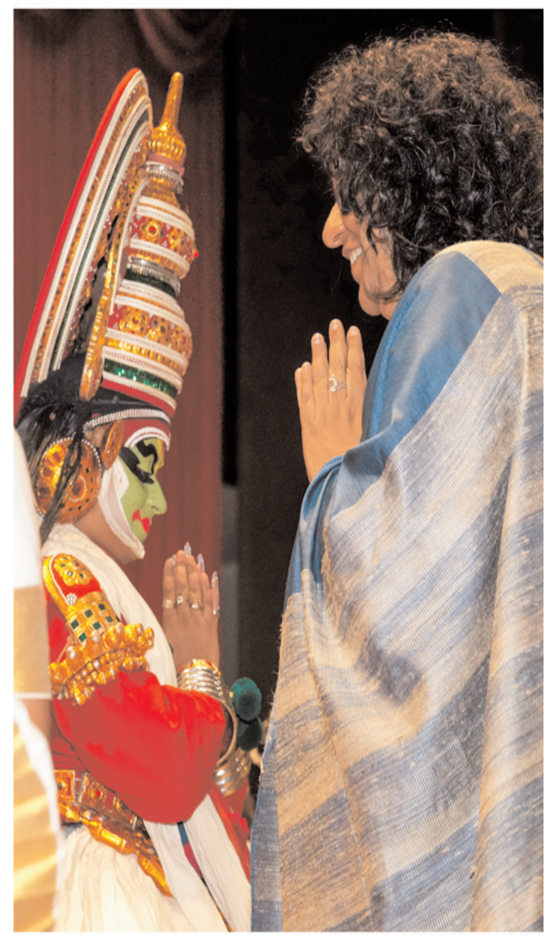

अभिवादन

श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या गुरुवार को नई दिल्ली स्थित हिंदू कॉलेज में अपने दौरे के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली 'कथकली' का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कलाकार से अभिवादन करती हुईं।

जलवायु संकट दुनिया भर में भीषण आग को बढ़ावा दे रहा

मेलबर्न। पृथ्वी के फेफड़े कहलाने वाले अमेज़न के घने जंगलों से उठते धुएं की भयावह तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं। स्पेन के अग्निशामक खेत में लगी आग से जूझ रहे हैं। लॉस एंजिलिस में मशहूर हस्तियों के घर धुएं से काले पड़ गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहर धुएं से भरे हैं।

अगर आपको लगता है कि पिछले साल जंगल की आग और उनके प्रभाव अधिक भीषण थे – तो आप सही हैं। हमारी नई रिपोर्ट, जो विभिन्न महाद्वीपों के वैज्ञानिकों के बीच एक सहयोग से तैयार हुई है, दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन ने अप्रत्याशित और विनाशकारी तरीकों से दुनिया में दावानल (जंगल की आग) के स्तर को और बढ़ा दिया है। मानव-जनित जलवायु परिवर्तन ने दुनिया के कुछ क्षेत्रों में जंगल की आग, जिसे ऑस्ट्रेलिया में बुशफ़ायर कहा जाता है, से जलने वाले क्षेत्र में 30 अप्रत्याशित वृद्धि की है।

हमारे अध्ययन में पिछले वर्ष लगी जंगल की आग के कारणों का पता लगाने और उनकी जांच करने के लिए उपग्रह प्रेक्षणों और उन्नत मॉडलिंग का उपयोग किया गया। शोध दल ने जलवायु और भूमि उपयोग परिवर्तन की भूमिका पर विचार किया और जलवायु तथा चरम घटनाओं के बीच एक स्पष्ट अंतर्संबंध पाया।

क्षेत्रीय विशेषज्ञों ने उन घटनाओं और प्रभावों को दर्ज करने के लिए स्थानीय जानकारी प्रदान की जिन्हें उपग्रहों ने नहीं पकड़ा था। ओशिनिया के लिए, यह भूमिका कंट्री फायर अथॉरिटी की डॉ. सारा हैरिस और मैंने निभाई।

पिछले वर्ष, भारत से भी बड़ा भू-भाग – लगभग 37 लाख वर्ग किलोमीटर – दुनिया भर में जल गया। इस आग से 10 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए, और 215 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत के घर और बुनियादी ढांचा खतरे में पड़ गया।

गर्म होती जलवायु का मतलब न केवल अधिक खतरनाक, आग लगने की संभावना वाली परिस्थितियां हैं, बल्कि यह वनस्पति के बढ़ने और सूखने के तरीके को भी प्रभावित करती है, जिससे आग फैलने के लिए ईंधन बनता है।ऑस्ट्रेलिया में, बुशफ़ायर हालांकि पिछले मौसमों, जैसे कि 2019-20 की ब्लैक समर बुशफ़ायर, के समग्र विस्तार या प्रभाव तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आग की 1,000 से ज़्यादा घटनाओं ने लगभग 4,70,000 हेक्टेयर और मध्य ऑस्ट्रेलिया में 50 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को जला दिया। विक्टोरिया में, ग्रैम्पियंस नेशनल पार्क का दो-तिहाई इलाका जल गया।

हमारे विश्लेषण से पता चला है कि अमेरिका में, जनवरी में लॉस एंजिलिस में लगी जंगल की आग की भयावहता दोगुनी थी और इसने ग्लोबल वार्मिंग के बिना जलने वाले क्षेत्र की तुलना में 25 गुना बड़ा क्षेत्र जला दिया।

पिछले 30 महीनों में लॉस एंजिलिस में असामान्य रूप से नम मौसम ने वनस्पतियों की तेज़ वृद्धि में योगदान दिया और असामान्य रूप से गर्म और शुष्क जनवरी के दौरान जंगल की आग की नींव रखी।

दक्षिण अमेरिका में, ब्राज़ील, बोलीविया और पराग्वे की सीमा पर स्थित पैंटानल-चिकिटानो क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण लगी आग 35 गुना बड़ी थी। रिकॉर्ड तोड़ आग ने अमेज़न और कांगो के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया, जिससे अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड निकली।

अभी देर नहीं हुई है

यह स्पष्ट है कि यदि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही, तो अधिक भीषण गर्मी और सूखे के कारण दुनिया भर में प्रचंड गर्मी की घटनाएं और भी तीव्र हो जाएंगी।

लेकिन अभी भी कार्रवाई करने में देर नहीं हुई है। हमें जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में कटौती, प्रकृति की रक्षा और भूमि की कटाई को कम करने के लिए मज़बूत और तेज़ जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता है। हम सूक्ष्म वन प्रबंधन से लेकर घरों की तैयारी और अल्पकालिक व दीर्घकालिक आपदा प्रबंधन तक, आग के जोखिम से निपटने में बेहतर हो सकते हैं।

आग लगने की घटनाओं में क्षेत्रीय अंतर होते हैं, इसलिए प्रतिक्रिया भी स्थानीय होनी चाहिए। हमें आग से निपटने में स्थानीय और क्षेत्रीय ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए।

सपना चौधरी ने नसीहत देने वालों को दिया जवाब

मुंबई/एजेन्सी

हरियाणवी डांसर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मशहूर शख्सियत सपना चौधरी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार वजह बना है उनका एक इंस्टाग्राम वीडियो, जिसमें वो पारंपरिक पटियाला सूट पहनकर गलियों में बड़े दिलकश अंदाज में घूमती नजर आ रही हैं। वीडियो में उनका देसी अंदाज लोगों को खासा पसंद आ रहा है। सपना चौधरी अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने डांस वीडियोज, शायरी और देसी लुक्स साझा करती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए दिल की बात भी साझा की है।

धोखाधड़ी के केस में शिल्पा शेट्टी को नहीं मिली लॉस एंजेलिस जाने की अनुमति

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) की वजह से शिल्पा को विदेशी यात्रा की अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते उन्होंने लॉस एंजेलिस जाने के प्लान को रद्द कर दिया। एक्ट्रेस ने यूट्यूब के एक इवेंट में जाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। उनके वकील ने बताया कि शिल्पा अपनी इस यात्रा की याचिका वापस ले रही हैं और दिसंबर में जब उन्हें फिर से विदेश जाना होगा, तब वे नई याचिका दाखिल करेंगी। धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके कारण दोनों की विदेश यात्रा पर रोक थी। कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बावजूद उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के वकील ने एक नया आरोप भी लगाया है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर लगाए गए आरोप 2015 से 2023 के बीच बिजनेसमैन दीपक कोठारी द्वारा कंपनी में 60 करोड़ रुपए निवेश करने से जुड़े हैं। कोठारी का आरोप है कि दोनों ने इन पैसों का इस्तेमाल व्यवसाय में करने की बजाय अपने निजी खर्चों में किया। उन्होंने दावा किया कि कंपनी ने लोन के रूप में पैसा लिया था, लेकिन बाद में टैक्स की परेशानी के कारण इसे निवेश के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। इस मामले में शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया, जिसे बाद में आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया।

प्रेम, बुद्धिमत्ता और नारी शक्ति का उत्सव है : कावेरी कपूर

मुंबई/एजेन्सी

क्या हर दिन बेटी दिवस नहीं होता? कावेरी के लिए शेखर कपूर का यह दिल को छू लेने वाला नोट – प्रेम, विरासत और कला का प्रतीक है फ़िल्मकार शेखर कपूर, जो जीवन के प्रति अपने काव्यात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में अपनी बेटी कावेरी कपूर की बचपन की एक प्यारी सी पुरानी तस्वीर के साथ एक बेहद भावनात्मक संदेश साझा किया। जिसमें वह मुक्का मारने वाली नक्काशी वाली एक दीवार के सामने मजाकिया चेहरे के साथ मस्ती से पोज़ दे रही हैं। यह पोस्ट पिता-पुत्री के कोमल, आनंदमय और शाश्वत रिश्ते के सार को खूबसूरती से दर्शाता है। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए इस संदेश की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरे सवाल से होती है क्या हर दिन 'बेटी दिवस' नहीं होता? इसके बाद शेखर कपूर ने प्रेम, गर्व और पिता-पुत्री के आध्यात्मिक संबंध पर एक दिल छू लेने वाला मनन साझा किया।

शेखर कपूर अपने शब्दों में बताते हैं कि कैसे कावेरी ने उनके जीवन को एक अर्थ दिया, और वह डोरी जिसने मुझे जीवन से जोड़ रखा। उनका यह संदेश एक भावनाओं से भरा संदेस प्रतीत होता है, जिसमें पिता अपनी बेटी के प्रति स्नेह और प्रशंसा व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे इस बात पर विचार करते हैं कि कैसे उनकी बेटी कावेरी कपूर, जो एक गायिका-गीतकार, अभिनेत्री और कवियत्री हैं, उनकी दुनिया में अर्थ, आधार और ज्ञान लेकर आई हैं। वो लिखते हैं, तुमने मुझे उससे कहीं ज़्यादा ज्ञान दिया जितना मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता था। सबसे ख़ास बात यह है कि कावेरी में वे जिस जटिल द्वंद्व को देखते हैं, उसे खूबसूरती से व्यक्त करने की उनकी क्षमता, एक युवा मन में बसी प्राचीन आत्मा। वे उसकी रचनात्मकता, करुणा और संवेदनशीलता को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, और बताते हैं कि कैसे उसकी आत्मा कविता, संगीत और जीवों के प्रति सहानुभूति के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करती है। संदेश के अंत में वे लिखते हैं काश मैं तुम्हें तब जानता होता... पर शायद मैं जानता था? इन शब्दों के साथ, शेखर कपूर पाठकों को एक टाइमलेस जुड़ाव का एहसास दिलाते हैं। यह पिता-पुत्री का बंधन अब कला के क्षेत्र में भी एक साथ जुड़ने जा रहा है। दोनों जल्द ही 'मासूम: द नेक्स्ट जेनरेशन' पर काम करने वाले हैं जो शेखर कपूर की प्रतिष्ठित कहानी कहने की परंपरा का अगला अध्याय है। इस प्रोजेक्ट में कावेरी कपूर एक अहम भूमिका निभाएंगी, जो पीढ़ियों के बीच एक रचनात्मक पुल का प्रतीक है। अपनी गहराई, संवेदनशीलता और आत्मीय कलात्मकता के साथ, कावेरी अपने पिता की दृष्टि में एक नया दृष्टिकोण जोड़ती हैं निरंतरता और परिवर्तन, दोनों का सुंदर संगम।

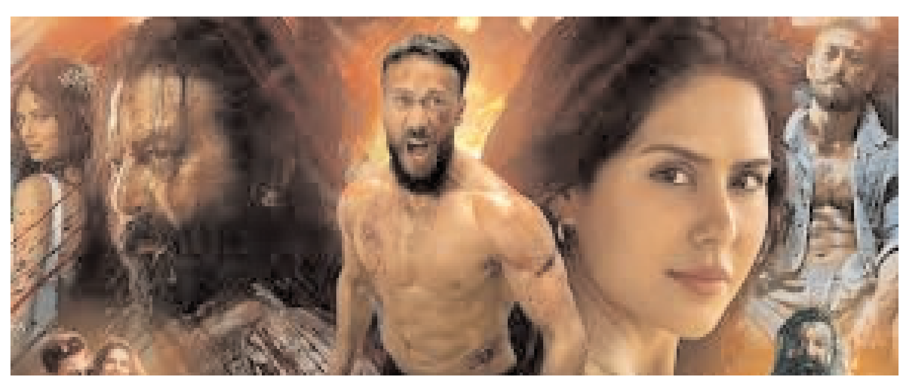

ओटीटी पर दस्तक देगी टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4'

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' ने पिछले महीने 5 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। एक्शन, थ्रिल और खून-खराबे से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। हालांकि जिन्होंने फिल्म थिएटर में मिस कर दी थी, उनके लिए अब खुशखबरी है, 'बागी 4' की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्माताओं ने फिल्म को दिवाली के खास मौके पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि 'बागी 4' के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो ने हासिल किए हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार फिल्म 17 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर रेंट पर उपलब्ध होगी, जबकि 31 अक्टूबर से सभी दर्शक इसे फ्री में देख सकेंगे। 'बागी 4' में टाइगर श्रॉफ के साथ संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू की यह बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म है। फिल्म का निर्देशन ए. हर्ष ने किया है, जबकि इसके निर्माता साजिद नाडियाडवाला हैं।

फिल्म ने भारत में 62.87 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि वैश्विक स्तर पर कुल कलेक्शन 77.67 करोड़ रुपये तक पहुंचा। 'बागी 4' एक्शन सीरीज़ की चौथी किस्त है।

इस फ्रेंचाइज़ी की पिछली तीन फिल्में 2016, 2018 और 2020 में रिलीज हुई थीं, जिनमें टाइगर श्रॉफ की एक्शन और स्टंट परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया था। अब दिवाली पर डिजिटल रिलीज के साथ दर्शकों को घर बैठे धमाकेदार एक्शन देखने का मौका मिलने जा रहा है। 'बागी 4' के ओटीटी डेब्यू से उम्मीद है कि यह फिल्म अपने रोमांचक दृश्यों और टाइगर श्रॉफ के पावरफुल एक्शन की वजह से ऑनलाइन दर्शकों के बीच नई लोकप्रियता हासिल करेगी।

बालिका वधू ने बनाया घर-घर का हिस्सा, उस पर गर्व है : अविका गौर

मुंबई/एजेन्सी

टीवी अभिनेत्री अविका गौर ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में शादी की। वह टीवी सीरियल 'बालिका वधू' के लिए आज भी याद की जाती हैं। इसमें उन्होंने आनंदी का किरदार निभाया था। उनका यह किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया। उन्होंने आईएएनएस के साथ एक खास बातचीत में बताया कि इस किरदार को जो प्यार लोगों ने दिया, उस पर उन्हें गर्व है। इसकी वजह से ही वह घर-घर फेमस हुईं। जब उनसे पूछा गया कि लोग उन्हें अब भी आनंदी कहकर पुकारते हैं, तो उन्हें कैसा लगता है? इसका जवाब देते हुए अविका गौर ने कहा, सच कहूं तो, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। अब यह मेरा दूसरा नाम जैसा लगता है। आज ही एयरपोर्ट पर एक अनजान महिला सामने आईं और मेरे गाल खींचते हुए मुझे आनंदी कहने लगीं। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे यह नाम देना बंद करें क्योंकि यह एक ऐसी पहचान है जो मुझे इस देश के हर घर से जोड़ती है। उस शो और उस किरदार ने मुझे कई परिवारों की बेटी बना दिया। मैं इसे हमेशा संजोकर रखूंगी। जब नेशनल टीवी पर अविका गौर की शादी होने जा रही थी, तब होस्ट सोनाली बेंद्रे ने उनसे एक सवाल पूछा था। सोनाली ने अविका से पूछा था, 'आपकी शादी सच में होने जा रही है? कैसा लग रहा है?' अविका गौर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझसे यह पूछा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरी परवाह है और वह यह सब कैमरे या रियलिटी शो के लिए नहीं पूछ रही हैं, बल्कि उनका हर वाक्य दिल से निकल रहा है। सोनाली मैम के साथ वह मेरे लिए बहुत ही खास पल था। उस दौरान मुझे लगा जैसे मुझे देखा, समझा और सहारा दिया जा रहा है। इसके बाद अविका गौर सोनाली बेंद्रे के गले लग गईं। उनको गले लगाने के बाद अविका गौर को लगा कि जैसे कोई फैमिली मेंबर उन्हें गले लगा रहा है। बता दें कि इस शादी में सारी रस्में निभाई गई थीं, शो के कंटेस्टेंट इसमें लड़के और लड़की के रिश्तेदार बनकर शामिल हुए थे।

मां की मेहनत देखकर फिल्मों से दूर रहना चाहती थीं काजोल

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल सिनेमा की उन सितारों में से हैं जिनकी पूरी पीढ़ी फिल्मी दुनिया से जुड़ी रही है। उनकी मां तनूजा अपने समय की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। पिता शोमू मुखर्जी फिल्म निर्माता थे, जबकि नानी शोभना समर्थ भी जानी-मानी अदाकारा थीं। हालांकि, हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में काजोल ने खुलासा किया कि वह कभी इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं। काजोल ने बताया, जब मैं बड़ी हो रही थी, मुझे एहसास हुआ कि मेरी मां बहुत संघर्ष करती थीं। वो सुबह 7 बजे से लेकर देर रात तक काम करती थीं, फिर भी उन्हें उतनी फीस नहीं मिलती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इतनी मेहनत कभी नहीं करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि यही वजह थी कि उन्होंने कभी फिल्मों में आने का सपना नहीं देखा।

काजोल ने कहा कि उन्हें फिल्मों की स्क्रिप्ट भले पसंद आ जाए, लेकिन कुछ विषयों से वो हमेशा दूर रहती हैं। उन्होंने साफ कहा, मैं रेप या छेड़छाड़ से जुड़े सीन नहीं करती। मुझे ऐसे विषय पसंद नहीं और मुझे नहीं लगता कि एक अभिनेत्री के तौर पर खुद को साबित करने के लिए ये जरूरी है। काम बात करें तो, काजोल इन दिनों चैट शो 'टू मच' को होस्ट कर रही हैं, जिसमें उनके साथ ट्विंकल खन्ना भी नजर आ रही हैं।

शिक्षा बननी चाहिए सबके सुख-शांति की आधार : आचार्य विमलसागरसूरी

गदग/दक्षिण भारत। राजस्थान जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ के तत्वावधान में विशाल धर्मसभा को मार्गदर्शन देते हुए आचार्य विमलसागरसूरीजी ने कहा कि मात्र साक्षर बन जाना या डिग्रियां प्राप्त कर लेना ही ज्ञानी होने का सार नहीं है। जो मनुष्य जीवन की संभावनाओं और उसके अर्थों को गहराई से समझाएं, वही सच्चा ज्ञान है। हम कितना जानते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं हैं, हम कैसा जीते हैं, यह महत्वपूर्ण है।

भारतीय संस्कृति ने उसे विद्या कहा है जो विनय और भलाई की सीख देती हो। जिससे अभिमान या चारित्रिक पतन की राह मिलती हो, वह जीवन के लिए अमृत नहीं, बल्कि ज़हर के तुल्य है। हमारी पढ़ाई या विद्वत्ता किसी भी व्यक्ति या प्राणी के शोषण अथवा पीड़ा का माध्यम नहीं बननी चाहिए। यदि हमें प्राप्त भरण-पोषण का सामर्थ्य किसी के शोषण का कारण बनता है तो वह दुःखदायी और दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय संस्कृति ने उसे ज्ञान, बुद्धि या पांडित्य नहीं माना है। ङ्गजैनाचार्य ने कहा कि आज मनुष्य का बुद्धि कौशल्य और ज्ञान अन्याय, अत्याचार, धूर्तता, विश्वासघात एवं ठगाई में लग रहा है। ज्ञान का भारी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है।

पढ़े-लिखे विद्वानों की बनिस्पत अनपढ़ लोग ज्यादा सरल, सहिष्णु और सेवाभावी दिखायी दे रहे हैं। पढ़-लिखकर मनुष्य स्वार्थी बन रहा है। बौद्धिक कुशलता छल-कपट के लिये नहीं हो सकती। आधुनिक युग में मनुष्य के भोलेपन को मूर्खता का दर्जा दिया जा रहा है। हकीकत में ज्ञान और शिक्षा सुख-शांति के आधार बनने चाहिए। सद्गुण ही मनुष्य के शिक्षित या ज्ञानी होने का सार है। अगर शिक्षित होकर भी मानवता नहीं महकती है तो शिक्षा कसरत से अधिक कुछ नहीं है। आचार्य विमलसागरसूरीजी ने कहा कि तीर्थंकरों और महापुरुषों के जीवन चरित्र केवल पढ़ने या व्याख्याओं के लिए नहीं होते, उनमें निहित रहस्यों और गुणों से सांप्रत समाज उन्नत बनना चाहिए।

ओम भिक्षु महाजप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के तेरापंथ महिला मंडल विजयनगर की सदस्याओं ने साध्वीश्री संयमलताजी के सान्निध्य में आयोजित हो रहे ओम भिक्षु महा जप अनुष्ठान के बैनर का अनावरण अर्हम भवन में किया गया। इस मौके पर मंडल की अध्यक्ष महिमा पटावरी ने अभातेयुप के नए अध्यक्ष पवन मांडोत व संगठन मंत्री रोहित कोठारी का सम्मान किया। उन्होंने बताया कि अर्हम भवन में सुबह एक घंटे का महाजप अनुष्ठान आयोजित हो रहा है। इस मौके पर अभातेममं की सहमंत्री मधु कटारिया, पूर्व महामंत्री वीणा बैद, महिला स्थानीय मंत्री सरिता छाजेड़, पूर्व अध्यक्ष मंजू गादिया, प्रेम भंसाली, जाप संयोजिका अंजू सेठिया सहित अन्य संस्थाओं के सदस्य उपस्थित थे।

चुनौतियों के बावजूद रायचूर विकास की आकांक्षा के साथ बढ़ रहा आगे : सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रायचूर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि रायचूर विभिन्न चुनौतियों के बावजूद विकास की आकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है और केंद्र राज्य के उत्तरी भाग में कल्याण कर्नाटक के क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। सीतारमण ने इस जिले के जवालगेरा गांव में कृषि प्रसंस्करण के लिए एक किसान प्रशिक्षण और साझा सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि इसी तरह के केंद्र सात जिलों में स्थापित किए जाएंगे। एक का उद्घाटन 15 अक्टूबर को कोप्पल में और आज (बृहस्पतिवार) रायचूर में किया गया।

उन्होंने कहा, ''इसी तरह, कल्याण कर्नाटक के सात जिलों में कुल सात कृषि प्रसंस्करण इकाइयां होंगी। ये इकाइयां सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) निधि और जिला प्रशासन के माध्यम से सरकारी सहायता का उपयोग करके, आईटीसी जैसी कंपनियों के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी में, किसानों से उत्पादों के विपणन और खरीद में मदद के लिए स्थापित की जा रही हैं।'' कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य सीतारमण ने कहा कि उनकी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) निधि से 3.5 करोड़ रुपये इन सात इकाइयों पर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार प्रसंस्कृत होने के बाद, ये उत्पाद रायचूर से लेकर बेंगलुरु तक राज्य में कहीं भी पहुंच सकते हैं और कर्नाटक के समग्र विकास में योगदान दे सकते हैं।

वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत बताते हुए कहा कि बेंगलूरु का विकास असाधारण रहा है, लेकिन रायचूर, अपने लोगों की कड़ी मेहनत के बावजूद, उसी गति से विकास हासिल करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। कर्नाटक की प्रगति के लिए रायचूर को एक प्रमुख केंद्र बिंदु बना रहना चाहिए। उन्होंने ऐसे जिलों के उत्थान के लिए केंद्र के प्रयासों पर जोर दिया, जिनमें विकास की क्षमता है, लेकिन विभिन्न चुनौतियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्हें 'पिछड़े जिले' कहने के बजाय, अब हम उन्हें आकांक्षी जिले कहते हैं।

मंत्री ने कहा, ''आज मैं देख सकती हूं कि रायचूर अपनी चुनौतियों के बावजूद, उन्हें एक-एक करके अवसरों में बदल रहा है। इसी तरह हम चुनौतियों को प्रगति के अवसरों में बदलकर सफलता प्राप्त करते हैं। रायचूर कई विकास संकेतकों पर सुधार दिखा रहा है। यह सफलता लक्षित हस्तक्षेप, सख्त निगरानी और समयबद्ध कार्यान्वयन का परिणाम है...।'' सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने विशेष दलहन कार्यक्रम शुरू किया है और रायचूर जैसे जिले दलहन की खेती को अपनाकर महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने देश भर में ऐसे 112 आकांक्षी जिलों की पहचान की है, जिनमें कर्नाटक के कल्याण जिले के रायचूर और यादगीर भी शामिल हैं। इसका मकसद उन्हें आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ने में मदद करना है। सीतारमण ने कहा कि 2023 की रैंकिंग में रायचूर 112 आकांक्षी जिलों में पहले स्थान पर है, जबकि जिले के मास्की ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में दक्षिणी राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा, हमने यहां किसान प्रशिक्षण और दलहन प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है क्योंकि रायचूर में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियां बहती हैं। यहां के किसान धान और दलहन दोनों की खेती करने में सक्षम हैं।

आत्मकल्याण का सच्चा मार्ग ही देता है जीवन को सार्थकता : डॉ वरुणमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के गुजराती जैन भवन में चातुर्मासिक प्रवचन में डॉ वरुण मुनिजी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मकल्याण का सच्चा मार्ग ही मानव जीवन को सार्थकता और शांति प्रदान करता है। जो व्यक्ति धर्म, सदाचार और आत्मचिंतन को जीवन का आधार बनाता है, उसका जीवन स्वतः ही दिव्यता से आलोकित हो उठता है। जब मनुष्य अपने भीतर झाँकता है और अपनी आत्मा के स्वर को सुनता है, तभी वास्तविक सुख और शांति का अनुभव होता है।

उन्होंने आगे कहा कि आज का मानव बाहरी सुख-सुविधाओं में आनंद खोजने की भूल कर रहा है, जबकि सच्चा आनंद आत्मशुद्धि और आत्मजागरण में ही निहित है। भौतिक उपलब्धियाँ क्षणभंगुर हैं, परंतु आत्मकल्याण की प्राप्ति शाश्वत आनंद प्रदान करती है। मुनिश्री ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे अपने जीवन में सत्य, संयम, करुणा और सद्भाव को अपनाएँ, क्योंकि इन्हीं गुणों के माध्यम से मनुष्य आत्मकल्याण की दिशा में अग्रसर हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान रूपेशमुनिजी ने भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी। उपप्रवर्तक पंकज मुनिजी म.सा. ने मंगल पाठ प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन राजेश मेहता ने किया।

सरलता से सिद्धि की प्राप्ति संभव : उपप्रवर्तक नरेशमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय मागडी रोड़ स्थित गुरु ज्येष्ठ पुष्कर दरबार में उपस्थित श्रद्धालुओं को उपप्रवर्तक नरेश मुनिजी ने उत्तराधयन सूत्र का वाचन करते हुए कहा कि धर्म को जानने के साथ उस पर आचरण करना भी जरूरी है। तभी धर्म श्रवण और जानने की सार्थकता सिद्ध होगी। जो भी चरम शरीरी जीव होते हैं वो अपने जीवन में धर्म साधना को प्रमुखता देते हैं। अतः भगवान महावीर की जगत के भव्य जीवों को अपने उपदेशों में कहा है कि धर्म को जानने के साथ उसे आचरण में लाने का भी प्रयास करें। उन्होंने सूत्र के अध्ययनों पर चर्चा करते हुए कहा कि जीवन के साथ, संयम साधना के मार्ग में भी परिषह उपसर्ग आते रहते हैं लेकिन कायर प्राणी उनका सामना नहीं कर पाता और अंत में हार जाता है, वहीं जो शूरवीर आत्मा होती है वो जीवन यात्रा, साधना में आने वाले सभी कष्टों, उपसर्गों, परिषहों को समभाव पूर्वक सहन करते हुए साधना मार्ग में अपने चरण गतिशील रखता है और सभी परिषहों पर विजय प्राप्त करते हुए अपने मुक्ति के मंजिल का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है।उन्होंने कहा कि धर्म भी शुद्ध हृदय में ठहरता है। कपट के साथ की गई साधना आपको मुक्ति नहीं दिला सकती है। सरलता का मार्ग ही निर्वाण की तरफ जाता है। सरल आत्मा की मुक्ति निश्चित होती है। उन्होंने कहा कि जब तक आपकी पुण्यवानी है तब तक संसार में आपकी चालाकी चल जाती है लेकिन जब पाप का उदय होगा फिर वहां कोई चतुराई नहीं चलेगी। व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का फल भोगे बिना इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती है। जो आत्म गुणों में रुचि रखे वो पर्याय धर्म है। उन्होंने कहा कि जो अपने स्वभाव में जीते हैं वो दूसरों के प्रलोभन में नहीं फंसते हैं। उन्होंने धर्म सभा में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों, माता पिता से यह आव्हान किया कि वे अपने बच्चों को दीवाली पर पटाखे नहीं चलाएं और पटाखों, आतिशबाजी का त्याग करने का संकल्प, नियम लेने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें छह काय जीवों को अभयदान देने की हित शिक्षा प्रदान करें। उन्होंने पटाखों के दुष्परिणामों को बताते हुए कहा कि इससे अपार जन धन की हानि के साथ धन का अपव्यय होता है। भगवान महावीर ने अहिंसा को परम धर्म बतलाते हुए जगत के सभी जीवों की रक्षा का संदेश दिया है। भगवान महावीर के उपदेशों, संदेश को मानकर चलने वाला ही उनका सच्चा अनुयायी कहलाने का अधिकारी बन सकता है। प्रारंभ में श्री शालिभद्र मुनि जी ने सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान महावीर की अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन स्वाध्याय सामूहिक रूप से सस्वर स्वाध्याय पारायण करवाया। उन्होंने शनिवार को साध्वी डॉ दर्शनप्रभाजी के जन्मोत्सव प्रसंग पर आयोजित 'गुरु पुष्कर दर्शन ट्राफी प्रश्न मंच प्रतियोगिता' की विस्तृत जानकारी देते हुए सबसे इसमें भाग लेने की प्रेरणा दी।

शरीर नहीं, आत्मा को सुंदर बनाने का करें प्रयास : संतश्री ज्ञानमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के यलहंका स्थित सुमतिनाथ जैन संघ के तत्वावधान में चातुर्मासार्थ विराजित संतश्री ज्ञानमुनिजी ने कहा कि प्रभु महावीर अनंत उपकारी हैं। उनके उपकारों की वजह से लाखों लाखों प्राणी धर्म मार्ग पर बढ़ते हैं और पाप मार्ग से बचते हैं। संसार में रह कर जो मानव पाप करने से बच गया उसका कल्याण निश्चित है। प्रभु के बताए मार्ग पर चलने वाला बहुत संयमी हो जाता है। उनकी कृपा से मोक्ष प्राप्त करने वाले महान लोगों के वर्णन के बारे में सुन रहे हैं। उत्तराध्यन सूत्र के 19वें अध्ययन में मृगा पुत्र का उल्लेख है जिसमें पूर्व भव के बारे में बताया गया है। कभी कभी बच्चों को पूर्व भव के बारे में याद आता है। मृगा पुत्र को पूर्व भव याद आया और वैराग्य लेने का मन जागा था। सांसों का कोई ठिकाना नहीं हैं चलते चलते भी निकल जाता है। जीवन सिर्फ तमाशा है। पानी में बतासा जैसा जीवन है। धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सांस के रुकते ही शरीर का भी मोल नहीं बचेगा, इसलिए जब तक सांस है आत्मा को तपा कर जीवन का उद्धार कर लेना चाहिए। बर्फ की दुकान वाला अगर सो जाएगा तो बर्फ गल जाएगा। वैसे ही शरीर का हाल है। वैसे ही मृग पुत्र ने संदेश दिया कि संसार दुखों का भंडार है। ङ्गमुनिश्री ने कहा कि संसार में जन्म के साथ मरण दुख है। संसार की सभी सुख की चीजें क्षण भर की होती हैं, इसलिए इसके मोह माया में नहीं लगना चाहिए। संसार की छोटी चीजों में उलझ कर मानव मूल चीज भूलता जा रहा है। संयम के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता है। लेकिन जो चला गया उसकी आत्मा का कल्याण निश्चित है। 21वें अध्ययन में समुद्रपाल का उल्लेख है। मनुष्य कितना भी कोशिश क्यों ना करे लेकिन कर्मों का फल तो जरूर मिलेगा। समुद्रपाल को अपराध देख कर दीक्षा लेने का वैराग्य आया था। उन्होंने संयम मार्ग धारण कर जीवन का कल्याण कर लिया। संयम बहुत सुखकारी होता है। संयम मार्ग पर चल कर जीवन बदल लेना चाहिए। कार्याध्यक्ष कांतिलाल तातेड़ ने सभी का स्वागत किया। सभा का संचालन महामंत्री मनोहरलाल लुकड़ ने किया।

जागरूकता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के अणुव्रत समिति के तत्वावधान में 'नम्मा बेंगलूरु स्वच्छ बेंगलूरु' अभियान के तहत सदस्यों ने बेंगलूरु वासियों से ईको फ्रेंडली दीपावली उत्सव मनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। गांधीनगर तेरापंथ भवन में मुनि डॉ पुलकित कुमारजी के सान्निध्य में पोस्टर का अनावरण कर सदस्यों ने शहर के विभिन्न स्थल जैसे बस स्टैंड, स्टेशन, मेट्रो स्टेशन आदि स्थानों पर लोगों के बीच जाकर स्वच्छ बेंगलूरु के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया तथा संकल्प दिलाया। समिति के अध्यक्ष ललित बाबेल, उपाध्यक्ष चंद्रशेखरय्या, कोषाध्यक्ष मनोहर मांडोत, मंत्री लाभेश कांसवा, सहमंत्री सुरेश चावत, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के अध्यक्ष हिम्मत मांडोत, महेन्द्र दक सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे।

दीपावली के पहले जीतो महिलाओं ने सीखे 'मीठे पकवान' बनाना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जीतो साउथ लेडीज़ विंग ने सक्षम अभियान के तहत 'हो जाये कुछ मीठा' कार्यक्रम जीतो कार्यालय में किया जिसमें 225 महिलाओं ने पाक कला सीखी। चेयरपर्सन बबीता रायसोनी ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज का सत्र सिर्फ़ कप केक बनाना सीखने के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन में मिठास घोलने की सीख है। दो सत्रों में आयोजित इस कार्यक्रम की संयोजिका सोमना सिसोदिया ने प्रशिक्षक मनीषा जैन का परिचय दिया। बेकसेक की संस्थापिका मनीषा ने बेकिंग की बारीकियाँ समझाईं। अपने सहयोगी समीक्षा जैन के साथ उन्होंने विभिन्न प्रकार के केक व चॉकलेट आदि बनाना सिखाया तथा बेकिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अनेक मिठाइयां बनाना व उनके मिश्रण के बारे में बताया। मुख्य सचिव निधि पालरेचा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। कोषाध्यक्ष संगीता पारख ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में केकेजी लेडीज़ विंग संयोजिका पिंकी जैन, स्मॉल हाउसहोल्ड बिज़नेस अपेक्स संयोजिका बिंदु रायसोनी और श्रमण आरोग्यम संयोजिका सुनीता गांधी विशेष रूप से उपस्थित थी। पिंकी जैन ने मैसूर में होने वाले आगामी लेडीज़ कॉन्क्लेव की जानकारी साझा की। गत दिनों हैदराबाद कनेक्ट के कुकिंग कम्पटीशन जीतो जायका नेशनल क्युलिनेरी क्वीन बनी साउथ लेडीज विंग के श्वेता बोकाड़िया को सम्मान किया गया। इस मौके पर विंग की उपाध्यक्ष लता बोहरा, संयुक्त सचिव साक्षी नाहर एवं चंद्रा जैन सहित अनेक सदस्याएं उपस्थित थीं। सहसंयोजिका अंगिका बाफना ने धन्यवाद दिया।

मैसूरु में जेबीएन मैसूर महाराजा रेफरल ग्रुप की बैठक सम्पन्न

मैसूरु/दक्षिण भारत । जीतो मैसूरु चैप्टर ने जीतो बिज़नेस नेटवर्किंग पहल के तहत बुधवार को जेबीएन मैसूर महाराजा रेफरल ग्रुप की पाक्षिक बैठक आयोजित की। जेबीएन(जैन बिजनेस नेटवर्क) जीतो की पहल है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक विकास को सशक्त बनाना है।

जेबीएन ग्रुप के टीम लीडर और जेबीएन संयोजक महावीर गादिया ने बैठक की अध्यक्षता की। जीतो के अध्यक्ष विनोद बाकलीवाल ने सभा का स्वागत किया।

चंद्रगुप्त कटारिया ने गत दिनों हैदराबाद में संपन्न हुए जीतो कनेक्ट कार्यक्रम की जानकारी दी। बैठक में केकेजी ज़ोन संयोजक चंद्रगुप्त कटारिया, अपेक्स के संयोजक पुनीत श्रीश्रीमाल, जीतो के मुख्य सचिव गौतम सालेचा, प्रेम पालरेचा, गौतम बाघमार, महिला विंग की अध्यक्ष मोना भटेवरा सहित मनीष शाह और अन्य सदस्य उपस्थित थे। अंत में पुनीत जुगराज ने धन्यवाद दिया।

तेयुप विजयनगर द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में दिखा विशेष उत्साह

अभातेयुप के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष व संगठन मंत्री का हुआ सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के अर्हम भवन में तेरापंथ युवक परिषद विजयनगर द्वारा बुधवार को अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद (अभातेयुप) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन मांडोत एवं संगठन मंत्री रोहित कोठारी का सम्मान किया तथा तेयुप विजयनगर को सर्वश्रेष्ठ परिषद का सम्मान प्राप्त होने का उत्सव मनाया गया।सान्निध्यता प्रदान कर रहीं साध्वी संयमलताजी ने कहा कि तेरापंथ धर्म संघ की संस्था किशोर मंडल से पनपा एक छोटा सा पौधा आज वटवृक्ष का आकार ले चुका है। अरमानों को आकाश, उम्मीदों को उल्लास देने वाली युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन मिल जाए तो उनकी प्रतिभा आसमान की ऊंचाइयों को छू लेती है। ऐसे ही प्रोत्साहन से किशोर मंडल से जुड़े पवन आज अभातेयुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और स्वयं के पराक्रम, पुरुषार्थ, लगन, जोश व जुनून के साथ आचार्यश्री की कृपा से आज उच्चाइयां प्राप्त की। तेयुप विजयनगर ने पूर्व अध्यक्ष कमलेश चोपड़ा ने सर्वश्रेष्ठ परिषद का खिताब मिलने पर सभी सहयोगी साथियों को धन्यवाद दिया। तेयुप के अध्यक्ष विकास बाँठिया ने सभी का स्वागत किया तथा नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। पवन मांडोत ने मिशन 2025-26 की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए स्थानीय सातों परिषदों को मिलकर कार्य करने का आव्हान किया। इस सम्मान कार्यक्रम में परिषद और संघ संस्थाओं के अनेक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर अभातेयुप सदस्य व विभिन्न तेयुप परिषदों के सदस्यों ने व्यवस्था संभाली। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक कावड़िया ने किया। अंत में सभी का आभार ज्ञापन मंत्री योगेश पोरवाड़ ने किया।

डिजिटल रूप में भी पढ़ें
दक्षिण भारत हिन्दी दैनिक
www.dakshinbharat.com

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**